घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 65- रविवार 04- जनवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

प्रधानमंत्री मोदी पवित्र पिपरहवा अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया

भगवान बुद्ध सबके हैं,सबको जोड़ते हैं : पीएम मोदी

नई दिल्ली,03 जनवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, सवा सौ साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस,भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा,भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहां मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं।

125 साल बाद बुद्ध के अवशेष भारत लाए गए : मोदी

पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की भारत वापसी पर कहा कि इन अवशेषों को अपने बीच पाकर हम धन्य है। 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है। अवशेषों का भारत से बाहर जाना फिर वापस आना एक बड़ा सबक है। गुलामी के काल में इन्हें भारत से छीना गया था। जो लोग इसे लेकर गए थे उनके ये केवल एंटीक थे इसलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने की भी कोशिश की। भारत ने तय किया कि हम इनकी नीलामी नहीं होने देंगे।

बुद्ध सबके हैं...सबको जोड़ते हैं...

प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान बुद्ध सबके हैं... सबको जोड़ते हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ, वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए,वो सारनाथ आज मेरी कर्मभूमि है। भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है,बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष बुद्ध के संदेश की जीवित उपस्थिति है।

पूरी मानवता का है भगवान बुद्ध का मार्ग...

मोदी ने कहा,भगवान बुद्ध का ज्ञान,उनका दिखाया मार्ग...पूरी मानवता का है। यह भाव हमने बीते कुछ महीनों में बार-बार अनुभव किया। बीते कुछ महीनों में भगवान बुद्ध के पावन अवशेष जिस भी देश में गए,वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया।

पीएम मोदी का 2026 का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम

2026 के शुरुआत में ही यह शुभ उत्सव बहुत प्रेरणादायी है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 2026 का ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है,जो भगवान बुद्ध की चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है कि भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सदभाव का नया दौर लेकर आए। जिस स्थान पर यह प्रदर्शनी लगी है वो भी अपने-आप में विशेष है। किला राय पिथौरा का यह स्थान भारत के गौरवशाली इतिहास की यशभूमि है।

भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पाकर हम सभी धन्य'

पीएम मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना... ये दोनों ही पड़ाव अपने-आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी कोई राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती,गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया। तब से करीब सवा सौ साल तक ये देश से बाहर ही रहे हैं। इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। भारत के लिए तो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष... हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस आठ जनवरी से देशभर में शुरू करेगी 'मनरेगा बचाओ संग्राम'

नई दिल्ली,03 जनवरी 2026। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि वह देशभर में 08 जनवरी से 25 फरवरी तक 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की शुरुआत करेगी। इसके तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम करने के साथ ही अलग-अलग हिस्सों में चार बड़ी जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। इस अभियान की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और महासचिव जयराम रमेश ने यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में संयुक्त रूप से की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया कानून वीबी- जी राम जी संविधान के अनुच्छेद 258 का उल्लंघन करता है और इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि यह कानून राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करता है और उन्हें योजना में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए बाध्य करता है। वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी के इस 'संग्राम' का मकसद यह है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) बहाल हो और नए कानून को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा देश की सबसे सफल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित गरीबी उन्मूलन योजना रही है, जिससे हर साल 5-6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलता है। संकट के समय यह गरीबों के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा कवच साबित होती है लेकिन वीबी-जी राम जी कानून के तहत रोजगार अब अधिकार नहीं रहा, बल्कि केवल केंद्र सरकार द्वारा चुनी गई पंचायतों तक सीमित कर दिया गया है।

मिठाई दुकान में हंगामे के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज,समाज पर अभद्र टिप्पणी का आरोप

एमपी,03 जनवरी 2026। जबलपुर के कमनिया गेट इलाके में एक मशहूर मिठाई की दुकान पर एक छोटा सा विवाद हंगामे में बदल गया, जिसके बाद जैन समुदाय के लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया। बाद में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यह घटना शुक्रवार रात कोटवाली पुलिस स्टेशन के इलाके में ऐतिहासिक कमनिया गेट के पास स्थित मशहूर मिठाई की दुकान पर हुई। शिकायतकर्ता राजकुमार जैन, जो एक स्थानीय बिजनेसमैन हैं, ने आरोप लगाया कि वह अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के साथ सामान खरीदने के लिए दुकान पर गए थे। उन्होंने शिकायत की कि परोसा गया खाने का सामान ठंडा था, जिससे दुकान के मैनेजर के साथ बहस हो गई। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई जब मैनेजर ने कथित तौर पर स्टाफ के सदस्यों को बुलाया, जिसके बाद जैन के परिवार को मौखिक रूप से गाली दी गई। पुलिस ने बताया कि कथित तौर पर पूरे जैन समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। अपमान से गुस्सा होकर, जैन और उनके साथियों ने स्टाफ का सामना किया।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव...बिना वोट पड़े 68 कैंडीडेट निर्विरोध जीते

बीजेपी के 44 उम्मीदवार,शिंदे के 22,बची सीटों पर 15 जनवरी को वोटिंग

मुंबई,03 जनवरी 2026। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की वोटिंग से 13 दिन पहले बीजेपी गठबंधन (महायुति) ने 68 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी को 44 सीटें मिलीं,एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 22 सीटें अपने नाम कीं। वहीं अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में दो सीटें आईं। नियमों के मुताबिक,अगर किसी सीट पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में रह जाता है और कोई दूसरा प्रत्याशी नामांकन नहीं करता या नाम वापस ले लेता है,तो उस उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इन 68 सीटों पर भी यही स्थिति बनी,इसलिए मतदान कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी अब 29 नगर निगम की बची हुई 2801 सीटों पर 15 जनवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 16 जनवरी को आएंगे।

सबसे ज्यादा बीजेपी कैंडीडेट कल्याण-डोंबिवली नगर निगम से जीते

बीजेपी के जो 44 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। वे सबसे ज्यादा ठाणे जिले के कल्याण-डोंबिवली नगर निगम से हैं। इसके बाद पुणे,पिंपरी चिंचवड़,पनवेल,भिवंडी,धुले, जलगांव और अहिल्यानगर नगर निगम से चुनाव जीते। पुणे के वार्ड नंबर 35 से बीजेपी उम्मीदवार मंजूषा नागपुरे और श्रीकांत जगताप निर्विरोध चुने गए। ये दोनों 2017 से 2022 के बीच भी इसी वार्ड से चुने गए थे।

वोटिंग से पहले जीत पर विपक्ष का रिएक्शन

एमएनएस नेता अविनाश जाधव ने कहा, अगर आप वोटिंग से पहले ही जीतना चाहते हैं तो चुनाव क्यों करवाते हैं। दोनों सत्ताधारी पार्टियों को इसे आपस में बांट लेना चाहिए। भारत और राज्य में लोकतंत्र खत्म हो गया है। उन्होंने विपक्ष के कमजोर उम्मीदवारों को चुना और अपना काम करवा लिया। शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने भी ऐसी निर्विरोध जीत सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी उम्मीदवारों पर दबाव डालने का आरोप सत्ताधारी पार्टियों पर लगाया।

बांग्लादेश में एक और हिंदू की मौत

खोकन चंद्र दास ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

ढाका,03 जनवरी 2026। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शरियतपुर जिले के बाजार में मेडिकल स्टोर चलाने वाले हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास की शनिवार सुबह ढाका के नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट में इलाज के दौरान मौत हो गई। नए साल की पूर्व संध्या पर हमलावरों ने उन पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। डॉक्टरों के मुताबिक, खोकन दास के शरीर का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा झुलस गया था। उनके चेहरे और श्वसन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा था। अस्पताल के प्रोफेसर डॉ. शौन बिन रहमान ने बताया कि सुबह करीब 7:20 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। यह घटना 31 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे दामुदिया उपजिला के कोनेश्वर यूनियन स्थित केउरभांगा बाजार के पास हुई। दुकान बंद कर घर लौट रहे खोकन दास को रास्ते में बदमाशों ने रोका, धारदार हथियारों से हमला किया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग से बचने की कोशिश में खोकन दास पास के तालाब में कूद गए। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे,जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें पहले शरियतपुर सदर अस्पताल और फिर ढाका रेफर किया गया था। खोकन दास की पत्नी सीमा दास,गोद में छोटे बच्चे को लिए फूट-फूटकर रोती नजर आईं। उन्होंने कहा मेरे पति रोज की तरह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके पति ने दो हमलावरों को पहचान लिया था, इसी वजह से बदमाशों ने उनकी हत्या की नीयत से पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला,राष्ट्रपति को पकड़ा

ट्रम्प बोले...मादुरो और उनकी पत्नी अब हमारे कब्जे में

काराकस,03 जनवरी 2026।अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं। उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। अमेरिका ने बीती रात करीब 2 बजे (भारतीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह 11:30 बजे) वेनेजुएला के 4 शहरों पर हमले किए थे। इस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने मिलिट्री ठिकानों और खास जगहों को निशाना बनाया।

वेनेजुएला में इमरजेंसी लागू : अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने बयान जारी कर कहा था कि वे जवाब देंगे। उन्होंने देशभर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था। उनके बयान जारी करने के 1 घंटे बाद ट्रम्प ने उन्हें पकड़ने का ऐलान किया। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी और वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही थीं। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक वेनेजुएला में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा था। अमेरिका यह भी दावा करता है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अवैध गतिविधियों और हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी के मुताबिक निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के खिलाफ न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में आरोप तय किए गए हैं।

प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर 12 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

प्रयागराज,03 जनवरी 2026। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में शनिवार भोर में लाखों श्रद्धालुओं के संगम डुबकी लगाने के साथ ही माघ मेला का भव्य और दिव्य शुभारंभ हो गया। पौष पूर्णिमा पर शनिवार दोपहर 12 बजे तक प्रयागराज में 12 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। आज ही पहला मुख्य स्नान-पौष पूर्णिमा का है। पूरा मेला भव्यता और दिव्यता का संदेश दे रहा है। इस दौरान देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाएंगे। सनातन धर्म में प्रयागराज का यह माघ मेला धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवसर पर यहां श्रद्धालुओं को संगम में स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला के शुभारंभ पर कल्पवासियों व श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। प्रशासन को अनुमान है कि आज पौष पूर्णिमा पर यहां 30 लाख से अधिक श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाएंगे। लाखों श्रद्धालु बीती रात ही संगम तट पर आ गए थे। आज सुबह मेला क्षेत्र में कई जगह भीड के कारण जाम जैसी स्थिति बन गई। हालांकि पूर्णिमा स्नान को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं और पूरे मेला क्षेत्र को सात सेक्टर के पांटून पुलों को वन-वे कर दिया गया है। बसाई गई है भव्य टेंट सिटीइस बार राज्य सरकार पिछले वर्षे के मुकाबले मेला को और अधिक भव्य व दिव्य बनाने की कोशिश में है। यही कारण है कि इस बार अधिक व्यवस्था और सुविधाएं की जा रही हैं। अगर हम टेंट सिटी की बात करें तो माघ मेले के लिए इस बार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में भव्य टेंट सिटी बसाई गई है जबकि पिछला माघ मेला 768 हेक्टेयर में था। प्रशासन ने तैयारियां इस हिसाब से की हैं कि इस बार करीब 15 करोड़ श्रद्धालु माघ मेले में पहुंचेंगे जबकि 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 6 करोड़ ही थी। उल्लेखनीय है कि महाकुंभ के कारण वर्ष 2025 माघ मेले का आयोजन नहीं किया गया था। पहली बार रिवर एम्बुलेंस की सुविधाश्रद्धालुओं के लिए सबसे खास सुविधा यह है कि माघ मेले के लिए 2 रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है जबकि 80 एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। इसके अलावा अस्पतालों की अपनी व्यवस्था और चिकित्सीय सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यहां कुशल डाक्टरों के साथ साथ पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनात का काम समय रहते पूरा कर लिया है।

देशभर में 2026 का दिखा पहला सुपरमून,सामान्य चांद से 14 गुना है बड़ा

कोलकाता,03 जनवरी 2026। देशभर में शनिवार की रात सबसे बड़ा चांद यानी सुपरमून दिखाई दे रहा है। यह 2026 का पहला सुपरमून है। इस दौरान चंद्रमा का आकार सामने से करीब 14 गुना बड़ा दिखा। साथ ही 30 प्रतिशत ज्यादा चमकीला भी नजर आया।सुपरमून को बिना किसी उपकरण के भी आसानी से देखा जा सकता है लेकिन अगर कोई दूरबीन या छोटा टेलिस्कोप इस्तेमाल करे, तो चांद की सतह की बनावट ज्यादा साफ नजर आती है। यह सुपरमून अक्टूबर से शुरू हुए चार महीनों के सुपरमून रन का आखिरी था। इसके बाद 2026 के अंत में अगला सुपरमून दिखेगा। सुपरमून तब होता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। इस वजह से चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। सुपरमून को देखने पर ऐसा लगा जैसे यह पृथ्वी के करीब आ रहा है। आमतौर पर चंद्रमा सबसे दूर 4,05,000 किलोमीटर और सबसे करीब 3,63,104 किलोमीटर दूर होता है।

खगोलीय भाषा में इसे सुपर वुल्फ मून कहा जाता है। जनवरी की ठंड में उत्तरी गोलार्ध में पहले भेड़ियों की आवाजें ज्यादा सुनाई देती थीं, इसलिए इस महीने की पूर्णिमा को वुल्फ मून नाम मिला।

क्या होता है सुपरमून .

सुपरमून एक ऐसी खगोलीय घटना है, जिसमें चांद अपने सामान्य आकार से ज्यादा बा। दिखाई देता है। सुपरमून हर साल तीन से चार बार देखा जाता है।

सुपरमून दिखने की वजह भी काफी दिलचस्प है। जब चांद धरती का चक्कर लगाते-लगाते उसकी कक्षा के बेहद करीब आ जाता है। इस स्थिति को पेरिजी कहा जाता है।

वहीं, चांद के धरती से दूर जाने पर उसे अपोजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नोल ने पहली बार 1979 में सुपरमून शब्द का इस्तेमाल किया था।

पूर्णिमा और सुपरमून में क्या रिश्ता है ?

हर 27 दिन में चांद पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। 29.5 दिन में एक बार पूर्णिमा भी आती है। हर पूर्णिमा को सुपरमून नहीं होता, पर हर सुपरमून पूर्णिमा को ही होता है। चांद पृथ्वी के आसपास अंडाकार रेखा में चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी हर दिन बदलती रहती है।

जुलाई में होता है सुपर बक मून

जुलाई में नजर आने वाले सुपरमून को बक मून भी कहा जाता है। हिंदी में बक का मतलब वयस्क नर हिरण होता है। ऐसा साल के उस समय के संदर्भ में कहा जाता है,जब हिरणों के नए सींग उगते हैं। वहीं, कुछ जगहों में जुलाई के सुपरमून को थंडर मून भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में बादल गरजना और बिजली ककना आम बात है।

संपादकीय

कानूनी अधिकार बने स्वच्छ पानी

17 साल में 20 करोड़ से ज्यादा मामले...

भारत में दूषित पेयजल का गंभीर संकट है,जिसमें 2005 से 20 करोड़ से अधिक जलजनित बीमारियों के मामले और 50,000 से अधिक मौतें दर्ज हुई हैं। इंदौर की हालिया घटना प्रशासनिक विफलता,खराब समन्वय और स्वतंत्र विनियमन की कमी को उजागर करती है। यह एक राष्ट्रीय संकट है,न कि कोई स्थानीय चूक। सुरक्षित पेयजल को संवैधानिक दायित्व और कानूनी अधिकार बनाने की आवश्यकता है...

भारत ने अपने पर्यावरणीय संकटों को मापना सीख लिया है। वायु प्रदूषण को एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिये रोजाना आंका जाता है। हीटवेव और बाढ़ सार्वजनिक विमर्श पर हावी रहते हैं,लेकिन जब पीने का पानी जानलेवा बन जाता है, तब प्रतिक्रिया खतरनाक रूप से देर से,सीमित और अल्पकालिक होती है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से हुई हालिया मौतें कोई अपवाद नहीं हैं,बल्कि एक गहरी प्रशासनिक विफलता का लक्षण हैं।

इंदौर की घटना देश के अलग-अलग हिस्सों में घट चुकी समान त्रासदियों की कड़ी है। गुजरात के महिसागर जिले में हाल में पीलिया का प्रकोप बोरवेल और नगरपालिका जलस्रोतों के दूषित होने से जुड़ा पाया गया। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में प्रदूषित नल जल पीने से लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ओडिशा के संबलपुर में 2014 के हेपेटाइटिस प्रकोप में लगभग 3,900 से अधिक लोग संक्रमित हुए और लगभग 36 लोगों की मौत हुई थी।

भारत में असुरक्षित पेयजल कोई स्थानीय चूक नहीं,बल्कि बार-बार उभरने वाला संकट है। इस संकट का पैमाना भयावह है। 2005 से 2022 के बीच भारत में तीव्र दस्त,टाइफाइड,वायरल हेपेटाइटिस और हैजा जैसी प्रमुख जलजनित बीमारियों के 20.98 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें 50,000 से अधिक मौतें हुईं। इसके अलावा नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार हर साल लगभग दो लाख लोग सुरक्षित पेयजल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण अपनी जान गंवाते हैं।

इसके बावजूद जल गुणवत्ता कभी भी उतनी राजनीतिक प्राथमिकता नहीं बन पाती,जितनी अन्य पर्यावरणीय संकेतक बनते हैं। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। अनुमान है कि देश के लगभग 70 प्रतिशत जलस्रोत दूषित हैं। दूषित पानी से होने वाली बीमारियां काम के दिनों की हानि,बढ़ते चिकित्सा खर्च और श्रम उत्पादकता में गिरावट का दुष्चक्र पैदा करती हैं। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार, इससे 3.77 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं और हर साल करीब 7.3 करोड़ कार्यदिवसों का नुकसान होता है।

इन प्रकोपों की जड़ अक्सर जलस्रोत नहीं,बल्कि वह यात्रा होती है, जो पानी स्रोत से नल तक तय करता है। कई शहरों में रिपोर्टें बताती हैं कि सीवर का पानी पेयजल पाइपलाइनों में मिल जाता है। यह शहरी शासन की एक जानी-पहचानी विफलता है। नगरपालिका विभाग अक्सर एक-दूसरे से कटकर काम करते हैं। सड़क निर्माण एजेंसियां बिना जल और सीवरेज विभागों से समन्वय किए खुदाई कर देती हैं।

भूमिगत उपयोगिताओं के सटीक और साझा नक्शों के अभाव में भारी मशीनें पेयजल पाइपों को तोड़ देती हैं और सीवर लाइनों को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। इससे सीवर का गंदा पानी जल पाइपों में चला जाता है और समस्या तब सामने आती है, जब तक जनहानि हो चुकी होती है। यह समन्वयहीनता शहरी अवसंरचना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से और गहरी हो जाती है।

कई बार नई पाइपलाइनें बिछा दी जाती हैं,जबकि नीचे मौजूद पुरानी, रिसती और जर्जर नेटवर्क व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। भारत शहरीकरण को तो बढ़ावा दे रहा है,लेकिन इसमें सुरक्षा प्रोटोकाल,निरंतर निगरानी और संस्थागत जवाबदेही को अनदेखा कर दिया है। जल क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी स्वतंत्र नियमन का अभाव है। बिजली क्षेत्र में राज्य विद्युत नियामक आयोग बनाए गए,ताकि सेवा प्रदाय और नियमन को अलग किया जा सके और मानकों का प्रवर्तन हो सके। शहरी जल आपूर्ति में ऐसी कोई समान व्यवस्था नहीं है। नगरपालिका ही पानी देती है,वही जांच करती है और वही तय करती है कि सब ठीक है या नहीं? यानी संभावित प्रदूषक और नियामक अक्सर एक ही इकाई होते हैं। जब कोई स्वतंत्र नियामक नहीं होता तो न तो नियम सख्ती से लागू होते हैं और न ही गलती पर सजा मिलती है। पानी की जांच के नतीजे जनता से छिपे रहते हैं और प्रदूषण को तब माना जाता है, जब लोग बीमार पड़ने या मरने लगते हैं।

इसलिए सरकार पहले से रोकथाम करने के बजाय हादसे के बाद ही मरम्मत करती है। यह नियामक कमजोरी एक कानूनी शून्य से भी जुड़ी है। जहां भारत ने खाद्य का अधिकार जैसे वैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए हैं, वहीं सुरक्षित पेयजल अब भी एक 'निहित' अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की न्यायिक व्याख्या से निकला है, न कि स्पष्ट सेवा मानकों वाले किसी प्रवर्तनीय कानून से।

दूषित पेयजल संकट से निपटने के लिए हादसे के बाद तात्कालिक उपाय करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत ऐसी व्यवस्था की है,जो समस्या पैदा होने से पहले ही उसे रोक सके। इसके लिए जमीन के नीचे की पाइपलाइनों का सही नक्शा होना चाहिए, पानी की आपूर्ति करने वालों और उसकी जांच करने वालों को अलग रखा जाना चाहिए और अमृत 2.0 में नल से साफ और सुरक्षित पानी पहुंचाने पर जोर देना होगा।

इंदौर की मौतें कोई चूक नहीं,चेतावनी हैं। भारत ने जिस गंभीरता से हवा की गुणवत्ता मापनी सीखी है,अब उसी गंभीरता से उसे अपने पीने के पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसे कल्याणकारी अनुग्रह नहीं,बल्कि संवैधानिक दायित्व और बुनियादी आर्थिक आवश्यकता के रूप में देखना होगा।

क्या चैतन्य बघेल की राजनीति में एंट्री तय?

- **जमानत के बाद बढ़ी लोकप्रियता सोशल मीडिया से सड़कों तक गूंजते नारे...**
- **छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया सवाल तेज़ी से उभर रहा है...क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल अब सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं?**

रवि सिंह
कोरिया,छत्तीसगढ़

चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद जिस तरह से वे सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बने हैं,उसने इस कयास को और बल दिया है,फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सऐप ग्रूपों तक चैतन्य बघेल जिंदाबाद के नारे अब केवल डिजिटल स्पेस तक सीमित नहीं दिख रहे,बल्कि जमीनी स्तर पर भी सुनाई देने लगे हैं, फिलहाल यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि चैतन्य बघेल की राजनीति में एंट्री तय है,लेकिन इतना साफ है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति ने उन्हें नजरअंदाज करना बंद कर दिया है, जमानत के बाद मिली लोकप्रियता, समर्थकों की भावनात्मक प्रतिक्रिया और जमीनी नारों ने यह संकेत दे दिया है कि यदि चैतन्य बघेल राजनीति में उतरते हैं,तो यह केवल पारिवारिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा,अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में कका के साथ पुत्र भी राजनीतिक मैदान में अपना जोहार कहता है या नहीं।

जमानत नहीं,
समर्थकों की नजर में न्याय की जीत

कांग्रेस समर्थकों और बघेल परिवार के करीबियों का मानना है कि केंद्रीय एजेंसियों के तमाम दबावों और कठोर कार्रवाई के बावजूद चैतन्य बघेल को जमानत मिलना न्याय और सत्य की जीत है,उनका तर्क है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति या परिवार का नहीं, बल्कि उस राजनीति का प्रतीक है जिसमें सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ती है, इस पूरे दौर को समर्थक कका के लिए सबसे पीड़ादायक समय बता रहे हैं,जहां एक पिता के रूप में भूपेश बघेल को मानसिक संघर्ष से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने न तो लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता किया और न ही दबाव के आगे झुके।

संघर्ष से सहानुभूति,
सहानुभूति से राजनीति?

छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह कोई नया फार्मूला नहीं है कि संघर्ष सहानुभूति राजनीतिक स्वीकार्यता में बदल जाए, विशेषज्ञ मानते हैं कि चैतन्य बघेल के मामले में भी यही प्रक्रिया दिखाई दे रही है जेल और जांच की प्रक्रिया ने उन्हें पहचान दी,जमानत ने उन्हें नैरेटिव दिया, सोशल मीडिया ने उन्हें मंच दिया यही कारण है कि अब सवाल उठने लगा है, क्या आने वाले समय में भूपेश बघेल के साथ-साथ उनका पुत्र भी मंच साझा करते नजर आएगा?

पिता के साथ पुत्र का जोहार?

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि यदि चैतन्य बघेल राजनीति में आते हैं, तो वे केवल मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि संघर्ष से निकले चेहरे के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, युवाओं के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस के लिए एक नया चेहरा और नया ऊर्जा स्रोत बन सकती है, खासकर तब जब पार्टी नेतृत्व और उत्तराधिकार को लेकर सवालों से जूझ रही है, हालांकि, अभी तक न तो चैतन्य बघेल और न ही भूपेश बघेल की ओर से राजनीति में औपचारिक एंट्री को लेकर कोई स्पष्ट बयान आया है।

राजनीतिक विश्लेषण
अवसर भी,जोखिम भी...

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चैतन्य बघेल की एंट्री...

अवसर
- सहानुभूति और युवा समर्थन का लाभ
- बघेल परिवार की मजबूत
- राजनीतिक विरासत
- कांग्रेस को एक नया चेहरा

जोखिम
- विपक्ष द्वारा वंशवाद का हमला
- कानूनी प्रक्रिया का राजनीतिक इस्तेमाल
- अपेक्षाओं का अत्यधिक दबाव

इन्दौर की जल-त्रासदी और प्रशासनिक लापरवाही का नंगा चेहरा

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली-92

स्वच्छता रैंकिंग में लगातार टॉप पर आने वाले इंदौर में दूषित पेयजल की वजह से हुई मौतें कथनी और करनी की असमानता की पोल खोलती भयावह लापरवाही का नतीजा हैं। स्थानीय लोगों का यह आरोप बेहद गंभीर है कि पानी की क्वॉलिटी को लेकर लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई और दुर्भाग्य से इतनी बड़ी वारदात के बाद भी अदालत को दखल देकर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का आदेश देना पड़ रहा है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं है और न ही इसे तकनीकी खामी कहकर टाला जा सकता है। यह घटना उस व्यवस्था का क्रूर और नंगा सच है,जो स्वच्छता के तमगों से सजी हुई है लेकिन भीतर से सड़ चुकी है। जिस शहर को लगातार सात वर्षों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाता रहा, वहीं दूषित पेयजल के कारण पंद्रह निर्दोष लोगों की मौत हो जाना पूरे तंत्र पर एक गहरा प्रश्नचिह्न है। यह त्रासदी साबित करती है कि चमकदार रैंकिंग और पुरस्कार जीवन की वास्तविक सुरक्षा का विकल्प नहीं हो सकते। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में सीवर का पानी मिल गया, जिससे हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। सौ से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए, सैकड़ों बीमार पड़े और अनेक परिवार हमेशा के लिए उजे गए। सभ्य समाज में यह कल्पना ही आत्मग्लानि से भर देने वाली है कि जिस पानी को जीवनदायिनी मानकर पिया गया, वही सीवर की गंदगी से मिला हुआ था।

सबसे अधिक पीड़ादायक तथ्य यह है कि यह सब अचानक नहीं हुआ। नागरिकों ने पहले ही दूषित पानी की शिकायतें की थीं। पानी के रंग, गंध और स्वाद में बदलाव की जानकारी दी गई थी,लेकिन नगर निगम,जलप्रदाय विभाग और स्वास्थ्य तंत्र कुंभकर्णी नींद में सोए रहे। प्रशासन तब हरकत में आया जब मौतें हो चुकी थीं। यह लापरवाही नहीं,बल्कि गहरी संस्थागत असंवेदन शीलता, क्रूरता एवं अमानवीयता है। यह उस प्रशासनिक संस्कृति का परिणाम है जिसमें फाइलें और औपचारिकताएं मानव जीवन से अधिक मूल्यवान हो गई हैं। सवाल यह नहीं है कि पानी में सीवर कैसे मिला,असली सवाल यह है कि चेतावनियों के बावजूद इसे रोका क्यों नहीं गया? हर बार की तरह इस बार भी जांच समितियां बनीं,मुआवजे की

घोषणाएं हुईं और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। भले ही अपर नगर आयुक्त को इंदौर से हटा दिया है और प्रभारी अधीक्षण अभियंता से जिम्मेदारी वापस ले ली है। लेकिन,क्या इतना काफी है? इस तरह की 'रूटीन' कार्रवाई जिम्मेदारों को सबक नहीं देतीं, बल्कि पीड़ितों का मजाक बनाती हैं। क्या इन दिखावे की कार्रवाइयों से मृतकों का प्रायश्चित हो गया? क्या इससे भविष्य में ऐसी घटनाएं रुकेंगी? सच्चाई यह है कि जांच समितियां अब जवाबदेही तय करने का नहीं,बल्कि मामले को ठंडा करने का माध्यम बन चुकी हैं। इस दुखद घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी ने लोगों के घावों को और गहरा किया। जिस क्षेत्र में यह त्रासदी घटी,उसके प्रतिनिधि और राज्य के नगरीय विकास मंत्री,जिनके अधीन पेयजल आपूर्ति का विभाग आता है,उनकी असंवेदन शील टिप्पणियों ने जनता के आक्रोश को बढ़ाया। बाद में खेद प्रकट किया गया,लेकिन सवाल यह है कि खेद से क्या उन परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया? यह सही है कि उमा भारती जैसी वरिष्ठ नेत्री ने दोषियों से प्रायश्चित और दंड की मांग की, लेकिन देश का अनुभव बताता है कि ऐसी मांगें अक्सर समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार का खूब प्रचार किया जाता है, लेकिन इंदौर की घटना ने दिखा दिया कि यदि व्यवस्था की पटरियां जर्जर हों,तो इंजन कितने भी हों, दुर्घटना तय है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधार,क्रियान्वयन और रूपांतरण की बात कही थी और जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रणालियों को अधिक अनुकूल बनाने पर जोर दिया था। लेकिन जब नागरिकों को स्वच्छ जल,स्वच्छ हवा, स्वस्थ चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं ही सुरक्षित रूप से उपलब्ध न हों, तो जीवनयापन को सुगम बनाने की बात खोखली लगती है। सर्वोच्च न्यायालय बार-बार स्पष्ट कर चुका है कि स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित जल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इंदौर की यह त्रासदी इस अधिकार का खुला उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पानी में जहरीला पदार्थ मिलाए और उससे लोगों की मौत हो जाए, तो वह गंभीर अपराध माना जाता है। फिर जब प्रशासन की लापरवाही से जहरीला पानी घर-घर पहुंचता है और लोगों की जान जाती है,तो उसे अपराध क्यों नहीं माना जाए? यह गैर-इरादतन हत्या से कम गंभीर मामला नहीं है।

इंदौर की घटना यह भी उजागर करती है कि स्वच्छता रैंकिंग, स्मार्ट सिटी के दावे और चमकदार प्रचार व्यवस्थागत नाकामी को छिपा नहीं सकते। सड़कें साफ हो सकती हैं, दीवारें रंगी जा सकती हैं,लेकिन यदि पाइपलाइनों के भीतर जहर बह रहा है,तो ऐसा विकास जनता के साथ छल है। यह समस्या केवल इंदौर तक सीमित नहीं है। देश के अनेक छोटे-बड़े शहरों में जर्जर पाइपलाइनें,अवैज्ञानिक सीवर व्यवस्था और भ्रष्ट ठेकेदारी तंत्र वर्षों से नागरिकों की जिंदगी के साथ खिलवो कर रहे हैं। कहीं हैजा फैलता है,कहीं पीलिया, कहीं दस्त और संक्रमण, लेकिन हर बार इसे स्थानीय समस्या कहकर टाल दिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इंदौर की पंद्रह मौतें भी प्रशासन को जगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं? क्यों नहीं ऐसी घटनाओं को आधार बनाकर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का बुलडोजर चलाया जाता? आज जब अवैध निर्माणों और गरीब बस्तियों पर बुलडोजर चल सकता है,तो प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं? क्यों उन अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं होते,जिनकी अनदेखी से लोगों की जान चली जाती है? क्यों सेवा से बर्खास्तगी और जेल की सजा जैसे कठोर कदम नहीं उठाए जाते?यह घटना पूरे देश के लिए चेतावनी है। सभी राज्यों और स्थानीय निकायों को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का गंभीरता से ऑडिट करना चाहिए। मुख्य पाइपलाइनों का नियमित निरीक्षण हो,सीवर और जल आपूर्ति लाइनों के बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित की जाए और यह स्पष्ट तय हो कि किस स्तर का अधिकारी किस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार होगा। जवाबदेही केवल कागजों में नहीं, व्यवहार में दिखनी चाहिए। जब तक लापरवाही को अपराध नहीं माना जाएगा और दोषियों को वास्तविक दंड नहीं मिलेगा,तब तक ऐसी त्रासदियां दोहराती रहेंगी। आज भी देश में हर एक लाख आबादी पर औसतन लगभग 35 लोगों की दूषित पेयजल की वजह से जान जाती है। ग्लोबल एवरेज की तुलना में यह लगभग तीन गुना है। बेशक सरकार ने जल जीवन मिशन जैसे अभियान चलाए हैं,जिसकी बदौलत करीब 81 प्रतिशत ग्रामीण घरों में टैप वॉटर पहुंचाने का दावा है, लेकिन अब भी सुधार की बहुत जरूरत है।

पूर्वोत्तर भारत की पीड़ा समझें,अपनेपन का अहसास कराना राष्ट्रीय कर्तव्य

त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में हुई मौत ने पूर्वोत्तर भारत के लोगों की समस्याओं को उजागर किया है। लेख घटना के राजनीतिकरण की आलोचना करता है और चकमा समुदाय के ऐतिहासिक संघर्षों पर प्रकाश डालता है। यह पूर्वोत्तर के विकास के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का उल्लेख करता है और राष्ट्रीय एकता व आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान करता है,ताकि पूर्वोत्तर के युवाओं को अपनेपन का एहसास हो...

तरुण विजय

त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में कुछ गुंडों के हमले में मौत की हृदयद्रावक घटना की पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। पूर्वोत्तर के सामाजिक संगठन,नेता इस घटना से काफी रोष में हैं। इस समय मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ही हूं,क्योंकि मुझे एंजेल चकमा के स्वजनों से मिलना है। इस घटना ने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं।

कुछ लोग इस घटना पर गिद्ध राज नीति कर दुर्भाग्य पूर्ण शोकातिका का असम एवं अन्य क्षेत्रों में आसन्न चुनावों के लिए जिस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, उससे समाज में विष बे ने का भय है। मृतक चकमा समाज का होनहार युवक था। चकमा मूलतः चटगांव निवासी, बौद्ध मतावलंबी एवं शांतिप्रिय लोग हैं। पंडित नेहरू की दुर्नीति के कारण चटगांव को गैर-मुस्लिम,हिंदू,बौद्ध बहुल होते हुए भी पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में जाने दिया गया। तब हजारों चकमाओं का नरसंहार हुआ। उन्हें शरण के लिए भारत आना पड़ा,लेकिन भारत के ईसाई बहुल पूर्वोत्तर राज्यों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। मिजोरम के ईसाई छात्र संगठनों ने 1990 के दशक में चकमाओं के घर जलाए और उन्हें त्रिपुरा सीमा के पार धकेल दिया। तब चकमाओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री भेजी थी। आज जो लोग एंजेल चकमा की हत्या को राजनीतिक रूप दे रहे हैं, उन्होंने कभी चकमाओं की विपत्ति समय में सहायता नहीं की।

चकमा लोग पूरे भारत में मात्र साढ़े पांच लाख हैं और मुख्यतःमिजोरम,असम,मेघालय, अरुणाचल,त्रिपुरा,पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। जहां वे ईसाई बहुल राज्यों में हैं,वहां उनके साथ भेदभाव होता है। उनके क्षेत्रों में सड़कें नहीं,स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। चकमा गांवों के नाम भी बदले गए हैं। इसलिए वे शिक्षा हेतु अपने बच्चे देहरादून,दिल्ली, बेंगलुरु आदि भेजने पर विवश होते हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे मनोरम, प्राकृतिक सुषमा से युक्त वीरों और प्रज्ञावान युवाओं का क्षेत्र है, जिसको राममनोहर लोहिया ने यक्ष प्रदेश कहा था। आठ प्रदेशों की पांच हजार किमी सीमाएं चीन, तिब्बत,म्यांमार,बांग्लादेश,भूटान और नेपाल से मिलती हैं। सर्वाधिक संख्या में प्रतिबंधित संगठन पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय हैं। मोदी शासन आने से पूर्व यहां

असम के अलावा अन्य राज्यों में रेल,हवाई अड्डे नामालूम थे। 2024-25 के बजट में पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का बजट 74.4 प्रतिशत बढ़ाया गया। 2014-15 की तुलना में मोदी शासन में पूर्वोत्तर के लिए कुल बजट 179 प्रतिशत बढ़ाया गया।

हवाई अड्डे, राजमार्ग, ईटानगर-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस,बेहतर शिक्षा एवं खेल सुविधाएं,इन सबका अनंत और असीम विस्तार हुआ है, पर इससे भारत के शत्रु तत्व और बौखला गए हैं। पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की षड्यंत्रकारी योजनाएं ब्रिटिश काल में क्राउन कालोनी के नाम से चलीं। ब्रिटिश काल में ही सादुल्लाह के नेतृत्व में असम की मुस्लिम लीग ने अपील जारी कर युवकों से ज्यादा बच्चे पैदा करने और असम में ज्यादा मुस्लिम भेजने का अभियान चलाया। असम तथा पूर्वोत्तर भारत पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बने, इसका षड्यंत्र रचा गया। एंजेल चकमा का परिवार एक देशभक्त और बौद्ध मतावलंबी है। वातावरण के कारण वहां कुछ परिवारों में पश्चिमी नाम रखने का अजीब फैशन है। इसलिए माइकल या एंजेल नाम सुनने में आते हैं। यह समय हर परिस्थिति में पूर्वोत्तर के युवाओं के साथ खड़े होने का है और उन्हें अपनेपन का अहसास कराना राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए। पूरे भारत के लिए देशभक्ति की कसौटी बने जांबाज सैनिक, विश्व कीर्तिमान बनाने वाले खिलाड़ी, गायक,विज्ञान और आतिथ्य व्यवसाय के अप्रतिम सितारे पूर्वोत्तर ने दिए हैं। उनकी श्रेष्ठ,गहरी निष्ठा भारत के तिरंगे के प्रति इतनी है कि वे हमें देशभक्ति का पाठ सिखा सकते हैं,पर उत्तर भारत से कितने लोग पूर्वोत्तर भारत पर्यटन के लिए जाते हैं? कितने यहां के सुंदर स्थानों,महापुरुषों,नदियों और पर्वतों के बारे में सामान्य जानकारी भी रखते हैं? कितने ऐसे हैं,जो यहां के कोई त्योहार बता सकें? कितनों को यहां के कोई दो नाम सही से बोलना आता होगा?

पूर्वोत्तर केवल सामरिक महत्व का विषय नहीं। यहां रक्तबंधु भारतीय हैं। यहां भारत का प्रथम सूर्योदय होता है। यहां की वेशभूषा, त्योहार सबसे सुंदर और अत्यंत मनमोहक हैं।

यहां के छात्र मेधावी भारतीय भविष्य के सर्जक हैं। वे देश के दुश्मनों से लोहा लेने में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। उनकी भाषाएं मधुर संगीत के समान हैं। उन्होंने रानी गाइदिन्ल्यू,यू तीरोट (तीरथ) सिंह,मनीराम दीवान जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानी दिए। उन्होंने कारगिल संघर्ष से लेकर प्रत्येक भारत रक्षा अभियान में अपने जीवन की आहुतियां दी हैं। वे चिंकी, मोमो नहीं,भारत माता के मुकुट मणि हैं,जो नूतन भारत निर्माता हैं। उनके प्रति आत्मीयता का भाव जगे, इसके लिए सभी राज्यों के विद्यालयों में पूर्वोत्तर भारत परिचय पाठ्यक्रम होने चाहिए। जहां कहीं पूर्वोत्तर भारत के छात्र बड़ी संख्या में हैं, वहां पुलिस का पृथक पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ बने,जिसमें पूर्वोत्तर से जुड़ा कोई अधिकारी प्रमुख हो एवं पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्वोत्तर की सम्यक जानकारी देने का अभ्यास वर्ग बने। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक संस्थान में पूर्वोत्तर भारत पर विशेष पाठ्यक्रम हो एवं नवीन अधिकारियों को दो माह का पूर्वोत्तर भ्रमण कराया जाए। सबसे बड़ी बात अपने परिवारों में माता-पिता बच्चों के साथ पूर्वोत्तर की चर्चा करें और छुट्टियां मलेशिया, सिंगापुर या यूरोप में नहीं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय में मनाने का मन बनाएं।

राष्ट्रीय एकता भाषणों अथवा बजट से नहीं, हृदय की ऊष्मा और पारस्परिक बंधुता के धागों से बुनी जाती है। नस्लीय हमलों की शब्दावली इस एकता वस्त्र को तार-तार करती है। एंजेल चकमा के हत्यारों को शीघ्र कठोर दंड मिले और घृणित मानवता विरोधी अपराधों की पुनरावृत्ति न हो, यही उस होनहार छात्र को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

कविता

मोनिका डागा आनंद
चेन्नई, तमिलनाडु

मंजिल जरूर मिलेंगी

नव वर्ष ने दी है दिलों में दस्तक प्यारी,
उमंगित हुई फिर से ये जिंदगानी सारी,
करेंगे फिर से ख्वाबों को पाने का प्रयास,
बदलेंगे असफलताओं का पुराना इतिहास ।

संकल्प शक्ति के रथ पर होकर सवार,
भरेंगे हम रंग रंगीन सपनों में बेशुमार,
हक़ीक़त को हौसलों से फिर से बदलेंगे,
अपनी अभिलाषाओं को जीवंत करेंगें ।

क्यों रूके और माने हम सरलता से हार,
हार को जीत में बदल सकते हैं हम यार,
जज़्बा हमारा कम तनिक भी नहीं होगा,
रोशन मुकम्मल जहाँ हमें एक दिन मिलेगा ।

हमारा संघर्ष जितना होगा अधिक गहरा,
अंत में देगा वो अनंत "आनंद" भी सुनहरा,
साधना सुकर्मों की सफ़लतम अवश्य होगी,
एक न एक दिन हमें मंजिल जरुर मिलेंगी ।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

CMYK

डिजिटल शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को मिले 5 कंप्यूटर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
राजभवन रायपुर में 2 जनवरी को राज्यपाल रमेन डेका ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, लखनपुर को डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए 5 कंप्यूटर सिस्टम प्रदान किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यालय में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना की और भविष्य में फिर से कस्तूरबा गांधी विद्यालय आने की इच्छा व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि 6 अक्टूबर 2025 को पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में राज्यपाल ने लखनपुर का दौरा किया था और विद्यालय में डिजिटल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रदान करने की घोषणा की थी। जिसे उन्होंने पूरा किया। राज्यपाल ने विद्यालय की अधीक्षिका अनुराधा सिंह को रायपुर राजभवन में आमंत्रित कर स्वयं कंप्यूटर सिस्टम प्रदान किए।

पति से विवाद के बाद महिला ने कीटनाशक सेवन कर दी जान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
शंकरगढ़ के मानपुर में 31 दिसंबर को शराब के नशे में पति-पत्नी के बीच विवाद हो गई थी। गुस्से में पत्नी ने कीटनाशक सेवन कर लिया था। परिजन उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बेनोती तिर्की पति प्रभु तिर्की उम्र 44 वर्ष शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुर की रहने वाली थी। 31 दिसंबर को पति-पत्नी शराब का सेवन किया था। इस बीच दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में पत्नी ने कीटनाशक सेवन कर लिया। परिजन उसे इलाज के लिए शंकरगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया। यहां चिकित्सक ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

शराब के नशे में पति ने पत्नी को पीटा,मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
सूरजपुर जिले के नमतगिरी में 30 नवंबर को शराब के नशे में पति ने पत्नी की बेदम पिटाई कर दी। उसे अस्पताल में भर्ती तक नहीं कराया गया। महिला घायल अवस्था में रिश्तेदार के घर पहुंची और उसे इलाज के लिए सूरजपर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टर ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विफईया पति वसंत कंवर उम्र 45 वर्ष सूरजपुर जिले के ग्राम नमतगिरी का रहने वाली थी। 30 दिसंबर को शराब के नशे में पति ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी थी। इससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी और उसे अंदरूनी चोट लगी थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती तक नहीं कराया गया। महिला किसी तरह सरस्वतीपुर अपने रिश्तेदार के घर पहुंची। जहां रिश्तेदार ने उसे इलाज के लिए सूरजपुर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टर ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

लर्निंग लाइसेंस हेतु विशेष शिविरों का आयोजन

-संवाददाता-
बलरामपुर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत् परिवहन एवं पुलिस विभाग के द्वारा लर्निंग लायसेंस शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत 7 जनवरी को सबाग,तहसील कार्यालय सामरी,कुसमी में एक दिवसीय शिविर, तहसील कार्यालय कुसमी,शंकरगढ़,राजपुर में 8 एवं 9 जनवरी को दो दिवसीय, रामानुजगंज में 11 एवं 12 जनवरी, पुराना बस स्टैंड बलरामपुर में 7 एवं 8 जनवरी, तहसील कार्यालय वाड्रफनगर में 11 एवं 12 जनवरी को शिविर आयोजित किया जाएगा। जो भी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, दसवीं का मार्कशीट लेकर उपस्थित होंगे। लाइसेंस के लिए (शासकीय शुल्क एवं परिवहन सुविधा केन्द्र शुल्क) एक केटैगरी लाइसेंस 400 रूपये, दो केटैगरी लाइसेंस 500 रूपये शुल्क निर्धारित है।

गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर शहर में निकला भव्य नगर कीर्तन..आस्था-अनुशासन-सेवा का अनुपम संगम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सिख समाज द्वारा शनिवार को भव्य नगर कीर्तन (शोभायात्रा) का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन का शुभारंभ दोपहर 2 बजे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से हुआ। यह शोभायात्रा महामाया चौक, सदर रोड,जय स्तंभ चौक,पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए गुरुद्वारा गुरु नानक निवास पहुंची। तत्पश्चात नगर कीर्तन गुरुद्वारा गुरु नानक निवास से ब्रह्म रोड एवं देवीगंज रोड होते हुए पुनः गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा पहुंची, जहां रात्रि में समापन हुआ। इस शोभायात्रा में पंज प्यारों के रूप में सतपाल सिंह छाबड़ा, गुरसेवक सिंह,नवराज सिंह बाबरा, हरमिंदर सिंह भामरा और गुरमीत सिंह भामरा शोभायमान थे और निशान साहिब की सेवा जसमीत सिंह छीना और गुरजोत सिंह चावला थे। नगर कीर्तन के दौरान गुरुवाणी की मधुर गूंज,कीर्तन और एक स्वर में संगत की अरदास ने पूरे नगर को आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर कर दिया। मार्ग में खड़े नागरिक भी श्रद्धा से नतमस्तक होकर इस दिव्य आयोजन के साक्षी बने।

कार्यक्रम के समापन पश्चात गुरु का अटूट लंगर श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक वितरित किया गया,जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं नगरवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर गुरु सिंह सभा के प्रधान गुरचरण सिंह छाबड़ा और सचिव हर्षप्रीत सिंह धन्जल सहित समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी जगदीप सिंह छाबड़ा ने दी है।

गतका रहा आकर्षण का केन्द्र...

इस अवसर पर इंटरनेशनल गतका ग्रुप 'दलेर खालसा' द्वारा प्रस्तुत गतका (सिख मार्शल आर्ट) का शानदार और रोमांचक प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा, जिसने उपस्थित संगत एवं नगरवासियों का मन मोह लिया। नगर कीर्तन में बच्चे, युवा, महिलाएं एवं बुजुर्ग सभी ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की और सेवा, समर्पण एवं अनुशासन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। पूरे आयोजन में सिख मर्यादा, अनुशासन और सेवा भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली।

अवैध धान खरीदी-बिक्री गिरोह का पर्दाफाश,पटवारी समेत दो गिरफ्तार

-संवाददाता-
बलरामपुर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध धान परिवहन और खरीदी-बिक्री के एक संगठित नेटवर्क का खुलासा करते हुए फिर एकबार कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने एक पटवारी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। कार्रवाई से सरकारी खरीदी व्यवस्था में की जा रही गड़बड़ियों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सनावल में पूर्व में दर्ज अपराध क्रमांक 82/2025 अंतर्गत धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम

एवं 318(4), 61(2) बीएनएस के प्रकरण में पहले ही आरोपी श्याम सुंदर गुप्ता एवं उसके भाई शिवम गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। मामले की विवेचना के दौरान आरोपी श्याम सुंदर गुप्ता के मोबाइल की जांच की गई, जिसमें पटवारी संजय सोनी एवं राजेश कुमार की संलिप्तता सामने आई। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने श्याम सुंदर गुप्ता के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ की खरीदी मंडियों में अलग-अलग किसानों के खातों के माध्यम से बेचकर अवैध लाभ कमाने की बात स्वीकार की। इस पर पुलिस ने पटवारी संजय सोनी पिता नीलम सोनो, 32 वर्ष, निवासी सनावल तथा राजेश कुमार पिता जलदेव प्रसाद गुप्ता, 39 वर्ष, निवासी तालकेश्वरपुर थाना सनावल,जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस मामले की आगे भी गहन जांच कर रही है और अन्य संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

नवा बिहान नशामुक्ति जागरूकता अभियान की बैठक आयोजित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
नवा बिहान नशामुक्ति जागरूकता अभियान एवं परामर्श केंद्र के प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ समाज सेविका बीके विद्या बहन के नेतृत्व में बैठक आयोजित की। इस बैठक में पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा और वर्तमान वर्ष की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। नवा बिहान नशामुक्ति अभियान के संयोजक मंगल पाण्डेय ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो के समक्ष कार्ययोजना प्रस्तुत की, जिसके दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। नवा बिहान समन्वयक अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि अब जन जागरूकता के साथ रचनात्मक पहल की आवश्यकता है। बैठक के मुख्य अतिथि,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभागों और मीडिया की सहभागिता पर जोर दिया। इसके

साथ ही उन्होंने किशोरों और किशोरियों के साथ नैतिक मूल्यों पर एक अलग बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया। बैठक में प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी व नवा बिहान नशामुक्ति जागरूकता अभियान के सदस्य अजय तिवारी, मनोज भारती, संतोष दास ,उमाशंकर पाण्डेय, विजय शंकर तिवारी और संतोष कुमार विश्वकर्मा उपस्थित थे।

फर्जी हस्ताक्षर कर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी कराने का आरोप,अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 21 की वार्ड पार्षद विमला सोनी के फर्जी हस्ताक्षर और नकली सील का उपयोग कर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किए जाने का मामला सामने आया है। पार्षद ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, वार्ड पार्षद विमला सोनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उनके वार्ड चोरकाकछार निवासी महिला विमला राजवाड़े की मृत्यु के संबंध में नगर पालिक निगम अम्बिकापुर द्वारा दो अलग-अलग तिथियों पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। पहला मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2025 को और दूसरा 7 अगस्त 2025 को जारी हुआ। दोनों प्रमाण-पत्रों में मृत्यु की तिथि अलग-अलग दर्शाई गई है। पार्षद के अनुसार 7 अगस्त 2025 को जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र में उनके लेटर पैड पर प्रमाणित-पत्र संलग्न है,जिस पर उनके वास्तविक हस्ताक्षर और सील मौजूद है। वहीं, 24 अप्रैल 2025 को जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र में उनके नाम से प्रमाणित किया गया है,लेकिन न तो वह उनके लेटर पैड पर है।

प्रशासन सतर्क,सुखरी समिति में 76 बोरी पुराना धान जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में तहसील अंबिकापुर अंतर्गत ग्राम कालापारा में पुराने धान के अवैध संकलन का मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार ग्राम कालापारा निवासी श्री महेंद्र प्रसाद राजवाड़े, पिता श्री चमरू द्वारा पुराना धान एकत्र कर सुखरी सहकारी समिति में लाया गया था। जांच के दौरान नियमों के विपरीत पाए जाने पर कुल 76 बोरी धान जब्त किया गया। जब्त धान को नियमानुसार सुखरी समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। इस अवसर पर राजस्व निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार

सिंह, पटवारी श्री रमेश कुमार मिश्रा,पटवारी श्री गया राम तथा कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही एवं पंचनामा तैयार कर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण की गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता, पुराने धान के मिश्रण अथवा अवैध भंडारण की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आंगनबाड़ी सहायिका पद पर प्राप्त नियुक्ति कलेक्टर ने की निरस्त

निष्पक्ष जांच के बाद पात्र अभ्यर्थियों की हुई नियुक्ति

-संवाददाता-
बलरामपुर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
जिले के शंकरगढ़ विकासखंड के आंगनबाड़ी केंद्र बहेराटोली,कटहरपारा,धाजापाठ व डूमरपानी में फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत अरमाना पति शमशेर आलम, रिजवाना पति अमरूद्दीन, प्रियंका यादव पति आशीष यादव व सुशीला सिंह पति उमाशंकर की नियुक्ति को अपील प्रकरण में बलरामपुर-रामानुजगंज कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा द्वारा निरस्त किया गया है। उनके द्वारा 15 दिवस के भीतर पात्र अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना शंकरगढ़ को दिए गए थे, जिसके अनुपालन में परियोजना अधिकारी शंकरगढ़ द्वारा उक्तानुसार चारों आंगनबाड़ी केंद्रों में पात्र अभ्यर्थियों (अपीलार्थीगण) के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र बहेराटोली में श्रीमती गायत्री पैकरा,कटहरपारा में अंजली तिर्की,धाजापाठ में सुषमा रवि व डूमरपानी में उर्मिला उरांव को आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्त किया गया है।

आंगनबाड़ी केंद्र बहेराटोली की अभ्यर्थी गायत्री पैकरा द्वारा की गई थी लिखित शिकायत : आंगनबाड़ी केंद्र बहेराटोली के अभ्यर्थी श्रीमती गायत्री पति हेमंत पैंकरा द्वारा आंगनबाड़ी भर्ती में हुए फर्जीवाड़ा की लिखित शिकायत अगस्त 2025 में कलेक्टर के समक्ष जनदर्शन में की गई। जिसके संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी शंकरगढ़ को दिए गए थे।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बीईओ कुसमी,शंकरगढ़ एवं राजपुर को शामिल करते हुए संयुक्त जांच दल गठित किया गया। संयुक्त जांच दल ने एक-एक दस्तावेजों का बारीकी से जांच किया साथ ही भर्ती प्रक्रिया में प्रस्तुत दस्तावेजों का विभिन्न कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर शीघ्रता से सत्यापन कराया और फर्जी होने के सम्बन्ध में अन्य जानकारियां संकलित किया। संयुक्त जांचदल ने जांचोपरांत फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त करने की अनुशंसा की थी। जिला शिक्षा अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी शंकरगढ़ के माध्यम से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को प्राप्त होने पर उन्होंने दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु परियोजना अधिकारी कुसमी को अधिकृत करते हुए निर्देशित किए।

फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर भेजा गया था जेल

उक्त मामले में थाना शंकरगढ़ में अरमाना, रिजवाना,प्रियंका,सुशीला व अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उक्त चारों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस द्वारा विवेचना में फर्जी अंकसूची अजीजी पब्लिक स्कूल भगवतपुर एवं कुसमी से तैयार कर जारी किया जाना पाए जाने पर समसुद्दीन अंसारी उसके पुत्र आबिद अंसारी,पुत्री शाहिना परवीन एवं अन्य 2 की भी गिरफ्तारी की गई थी।

त्वरित कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी शंकरगढ़ एवं जांचदल की रही सराहनीय भूमिका

कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने की जिम्मेदारी तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी शंकरगढ़ श्री करुण डहरिया को सौंपी थी। जिसे उन्होंने बखूबी से निभाते हुए मामले में त्वरित जांच,दोषियों पर सख्त कार्यवाही और पात्र अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया। इस पूरे प्रकरण में जांच दल में शामिल श्री रामपथ यादव (तत्कालीन बीईओ कुसमी) श्री आदित्य पाटनवार (तत्कालीन बीईओ राजपुर) श्री जय गोविंद तिवारी (तत्कालीन बीईओ शंकरगढ़) की सराहनीय भूमिका रही जिन्होंने सूक्ष्मता से निष्पक्ष होकर गोपनीयता बनाए रखते हुए जांच किया।

अग्निवीर भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी

जनवरी 2026 में धमतरी में होगी भर्ती,छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल....

-संवाददाता-
जशपुरनगर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ में जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी कर दिए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर द्वारा यह भर्ती रैली 10 से 24 जनवरी 2026 तक इंडोर स्टेडियम, धमतरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के पुरुष अभ्यर्थी भाग लेंगे। इस भर्ती रैली के अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं एवं 8वीं पास) पदों के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना द्वारा 30 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने के पात्र होंगे। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा रैली में सम्मिलित होने वाले योग्य अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www-joinindianarmy-nic-in पर अपलोड कर दिए गए हैं तथा अभ्यर्थियों के पंजीकृत ई-मेल पते पर भी भेजे गए हैं। भर्ती रैली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड, रैली अधिसूचना में उल्लेखित सभी आवश्यक दस्तावेज तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन साथ लाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक स्थित सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212 एवं 0771-2965214 पर संपर्क कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना में चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और चयन केवल योग्यता एवं प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। अभ्यर्थियों को दलालों एवं प्रलोभन देने वालों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

मयाली में एटीवी राइडिंग,स्पीड बोटिंग,कायकिंग व क्रिकेट के साथ इको-टूरिज्म का अनूठा उत्सव

-संवाददाता-
जशपुरनगर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
नया साल 2026 के पावन अवसर पर जशपुर वनमण्डल द्वारा मयाली नेचर कैम्प में पर्यटकों के लिए रोमांचक एडवेंचर एवं इको-टूरिज़्म गतिविधियों का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन वन विभाग द्वारा वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल तथा प्रकृति के बीच यादगार अनुभव प्रदान करना है। घने वनों, शांत जलाशय और हरियाली से आच्छादित मयाली नेचर कैम्प में इस नववर्ष पर साहसिक गतिविधियों की विशेष श्रृंखला तैयार की गई है। यहाँ आने वाले पर्यटक स्पीड बोटिंग,कायकिंग,एटीवी राइडिंग तथा क्रिकेट जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद उठा सकेंगे। इन सभी गतिविधियों के लिए नाममात्र शुल्क मात्र 100 रुपये प्रति गतिविधि निर्धारित किया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस आयोजन का हिस्सा बन सकें। वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल श्री शशि कुमार ने बताया कि सभी गतिविधियाँ प्रशिक्षित कर्मियों की निगरानी में एवं पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ संचालित की जाएंगी। इससे पर्यटकों को न केवल रोमांच का अनुभव मिलेगा, बल्कि वे पूरी तरह सुरक्षित माहौल में प्रकृति के करीब समय भी बिता सकेंगे। मयाली नेचर कैम्प का यह आयोजन इको-टूरिज़्म को बढ़ावा देने, स्थानीय वन समितियों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा जिले के पर्यटन को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह स्थान उन लोगों के लिए आदर्श है जो नए साल का स्वागत प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांच और सुकून के संग करना चाहते हैं। वन विभाग जशपुर द्वारा सभी नागरिकों एवं पर्यटकों से अपील की गई है कि वे नववर्ष के अवसर पर अपने परिवार एवं मित्रों के साथ मयाली नेचर कैम्प में पधारें। इन आकर्षक गतिविधियों का भरपूर आनंद लें तथा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अंबिकापुर प्रवास उपरांत कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मनेन्द्रगढ़ के साथियों का निलंबन बहाली धन्यवाद पत्र देकर आभार व्यक्त किया।

मौका देखकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा,पति को देख भागा आरोपी...महिला ने थाने में बताई आपबीती

-संवाददाता-
बलरामपुर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। रामानुजगंज थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,पीड़िता ने 2 जनवरी 2026 को रामानुजगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी जान-पहचान आरोपी उमेश सिंह से थी। आरोपी ने उससे शादी करने का झूठा वादा किया और 27 अक्टूबर 2025 की रात उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी वह अलग-अलग मौकों पर उसे बहलाकर शोषण करता रहा।

पति को देख भागा आरोपी : पीड़िता ने यह भी बताया कि 1 जनवरी 2026 को आरोपी ने रामानुजगंज बस स्टैंड के पास जबरन उससे बातचीत करने की कोशिश की। इसी दौरान जब पीड़िता का पति मौके पर पहुंचा, तो आरोपी उसे देखकर फरार हो गया। महिला की शिकायत के आधार पर रामानुजगंज थाना पुलिस ने दुष्कर्म से संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले। इसके बाद पुलिस ने आरोपी उमेश सिंह (30 वर्ष),पिता भागी सिंह, निवासी ग्राम गम्हरिया,चौकी विजयनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

पाकिस्तान में 7 इमरान समर्थकों को आजीवन कारावास की सजा

यूट्यूबर,जर्नलिस्ट और आर्मी अफसर भी शामिल,पूर्व पीएम की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन हिंसा भड़काई थी

इस्लामाबाद,03 जनवरी 2026। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक माने जाने वाले 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामाला इमरान की गिरफ्तारी के बाद 2023 में हुए हिंसक प्रदर्शनों से जुड़ा है। सातों पर राज्य संस्थानों के खिलाफ डिजिटल आतंकवाद में शामिल होने का मुकदमा चलाया गया। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और अशांति भड़काने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों का इस्तेमाल किया।

दोषी ठहराए गए लोगों में यूट्यूबर आदिल राजा,जर्नलिस्ट वजाहत सईद खान,साबिर शाकिर और शाहीन सहबाई, टेलीविजन एंकर हैदर रजा मेहदी, विश्लेषक मोईद पीरजादा और पूर्व सेना अधिकारी अकबर हुसैन शामिल हैं। यह फैसला इस्लामाबाद की एंटी-टेररिज्म कोर्ट के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने सुनाया। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं और मुकदमा

चलाने के लिए पाकिस्तान नहीं लौटे, इसलिए ट्रायल उनकी गैरमौजूदगी में हुआ। अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि अगर वे पाकिस्तान लौटते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाए।

इमरान समर्थकों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था : यह मामला 9 मई 2023 का है, जब इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के विरोध में देशभर में बड़े प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में सेना की इमारतों को आग लगाई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया,जिसके बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू की। पाकिस्तानी सरकार और सेना ने इमरान खान की पार्टी और विरोधी लोगों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है, आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों लोगों पर राज्य संस्थानों पर हमले और उकसाने के आरोप में मुकदमा चलाया गया है।

फिलहाल विदेश में रह रहे हैं सभी दोषी : अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इन सात लोगों ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर भडकाऊ भाषण दिए। राज्य विरोधी पोस्ट शेयर किए और राज्य संस्थाओं के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की। सजा पाने वाले सभी लोग इमरान सरकार हटने के बाद पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे और फिलहाल विदेश में रह रहे हैं।

कोर्ट 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

अदालत ने हर आरोपी को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने या छेड़ने की कोशिश और आपराधिक साजिश के दो आरोपों में आजीवन कारावास की सजा दी। अदालत ने अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कुल 35 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा और हर आरोपी पर 15 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। अदालत के आदेश के अनुसार, जुर्माने का भुगतान न करने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी दोषियों को सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सात दिनों के अंदर अपील करने का अधिकार है। इस फैसले ने पाकिस्तान में प्रेस की आजादी और इमरान खान के समर्थकों पर कार्रवाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

जर्नलिस्ट सईद खान बोले...कभी समन नहीं भेजा गया, यह सब नाटक है

अदालत के फैसले पर न्यूयॉर्क में रहने वाले जर्नलिस्ट सईद खान ने एक बयान में कहा कि उन्हें 'कभी कोई समन नहीं भेजा गया, कभी किसी कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई, और अदालत ने कभी उनसे संपर्क नहीं किया।' रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा,'यह फैसला न्याय नहीं है। यह एक राजनीतिक नाटक है, जिसे गलत तरीके से विश्वसनीयता के बिना संचालित किया जा रहा है।'

इमरान खान 2 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं...

इमरान खान पर 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं और वे अगस्त 2023 से जेल में हैं। भ्रष्टाचार मामले में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें सरकारी गिफ्ट (तोशाखाना केस) बेचने और सरकारी सीक्रेट लीक करने जैसे आरोप शामिल हैं।

ईरान में व्यापक हो रहा है खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला...बढ़ती महंगाई ने बढ़ाया असंतोष

तेहरान,03 जनवरी 2026। आर्थिक संकट,अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और विकराल होती महंगाई के कारण फैले लोगों के असंतोष से जूझ रहे ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला व्यापक हो रहा है।खासतौर पर देश के समक्ष बढ़ते आर्थिक संकट ने मौजूदा स्थिति को और भी खराब बना दिया है। 28 दिसंबर से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन राजधानी तेहरान सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में जोर पकड़ रहा है। मीडिया समूह ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान की राजधानी में दो दिनों की शांति के बाद शुक्रवार रात तेहरान के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। मशहद और कोम जैसे पवित्र शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए।देश के अशांत दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र स्थित ज़ाहेदान में प्रदर्शनकारी शुक्रवार की नमाज़ के बाद सड़कों पर उतर आए और देश के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी की।

उल्लेखनीय है कि यह शहर साल 2022 के व्यापक विरोध प्रदर्शनों का एक प्रमुख केंद्र था जहां एकबार फिर विरोध प्रदर्शन में तेजी देखी जा रही है। मशहद, ज़ाहेदान, कजवीन, हमदान और तेहरान सहित कई शहरों में व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। जहां सुरक्षा बलों की हिंसा और काफी संख्या में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रदर्शनकारी कट्टरपंथी मौलानाओं का शासन खत्म करने की मांग करते हुए सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई पर निशाना साध रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा धड़ा रेजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग कर रहा है। अब तक देश के 22 प्रांतों के 46 शहरों में यह विरोध प्रदर्शन फैल गया है।तेहरान, यज्द, जंजन समेत करीब 10 विश्वविद्यालयों के छात्र इस आंदोलन में शामिल हैं।बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग भी इसमें शामिल है जिसने अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद कर इस आंदोलन को समर्थन दिया है। ईरान इंटरनेशनल ने मानवाधिकार समूहों का हवाला देते हुए बताया है कि अब तक कम से कम 7 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और 30 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुए इन प्रदर्शनों में अब तक 119 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बीच ईरान की करेंसी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गयी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में महंगाई दर 42.2 फीसदी तक पहुंच गई। खानेपीने की चीजों की कीमतें पिछले साल की तुलना में 72 फीसदी बढ़ गईं है, जबकि स्वास्थ्य और दवाइयों से जुड़ी चीजें 50 फीसदी महंगी हो गईं। इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें हिंसक तरीके से मारता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट साझा कर कहा कि, हम कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने अमेरिकी हमले की स्थिति में उसके बेस को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने शुक्रवार को कहा है कि अगर अमेरिका आक्रामक कदम उठाता है तो उसके सैन्य ठिकानों को वैध निशाना माना जाएगा।

नेपाल में चुनाव सुरक्षा प्रबंध के लिए डेढ़ लाख अस्थाई सुरक्षाकर्मी की भर्ती प्रक्रिया शुरू

काठमांडू,03 जनवरी 2026। नेपाल में आगामी पांच मार्च को होने जा रहे आम चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने अस्थाई निर्वाचन पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। शनिवार को नेपाल पुलिस और सशस्त्र प्रहरी बल की तरफ से अपने-अपने स्तर से भर्ती किए जाने वाले जनशक्ति से संबंधित अलग-अलग प्रस्ताव गृह मंत्रालय से स्वीकृत होने के साथ भर्ती प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही दोनों पुलिस बल ने देशभर के जिला पुलिस कार्यालयों को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार रविवार तक सभी जिला पुलिस मुख्यालयों से भर्ती प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक आह्वान किया जाएगा। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता, पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) अविनारायण काफ्ले ने बताया कि गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने नेपाल पुलिस को 1 लाख 34 हजार निर्वाचन पुलिस भर्ती करने की अनुमति दी है, जबकि सशस्त्र पुलिस को 15 हजार की भर्ती की इजाजत होगी। नेपाल पुलिस ने 1 लाख 37 हजार 644 और सशस्त्र पुलिस ने 16 हजार की मांग की थी,

लेकिन गृह मंत्रालय ने दोनों की मांग कुछ कम कर मंजूरी दी है। निर्वाचन पुलिस की भर्ती के लिए वित्त मंत्रालय ने दोनों पुलिस बलों के लिए बजट सुनिश्चित कर दिया है। स्वीकृत बजट के आधार पर ही मापदंड तैयार किए गए हैं। तैयार मापदंड के अनुसार, भर्ती के बाद निर्वाचन पुलिस को 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद एक महीने तक उन्हें निर्वाचन ड्यूटी में तैनात किया जाएगा। नेपाल पुलिस द्वारा भर्ती की गई जनशक्ति नेपाल पुलिस के साथ और सशस्त्र पुलिस द्वारा भर्ती की गई जनशक्ति सशस्त्र पुलिस बल के साथ ही कार्य करेगी। उन्हें पुलिस जवानों के समान सेवा सुविधाएं मिलेंगी।

CMYK

आदिवासी छात्रों के हक पर डाका

खड़गवां एकलव्य घोटाले में वर्षों बाद कार्रवाई

दोषी निलंबित

एकलव्य विद्यालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा...2023 की खबरें हुई सच साबित,गुम फाइल से खुली पोल...

सत्ता के साये में दबा रहा आदिवासी शिक्षा घोटाला,अब खड़गवां एकलव्य मामले में प्रशासन जागा...

कांग्रेस काल में जांच,भाजपा शासन में कार्रवाईः खड़गवां एकलव्य भ्रष्टाचार केस में बड़ा मोड़...

आदिवासी बच्चों की थाली से चोरीः खड़गवां एकलव्य विद्यालय घोटाले में जिम्मेदारों पर शिकंजा...

फाइलें गुम,हक लुटाः खड़गवां एकलव्य स्कूल घोटाले ने खोली सिस्टम की परतें...

-रवि सिंह-

एमसीबी/खड़गवां,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के खड़गवां विकासखंड में संचालित एकलव्य आदिवासी आवासीय विद्यालय पोड़ीडीह में वर्षों तक चले कथित भ्रष्टाचार के मामले में आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई का डंडा उठाना शुरू कर दिया है,आदिवासी छात्र-छात्राओं को मिलने वाली शासकीय सुविधाओं में हुई गंभीर अनियमितताओं को लेकर जिन खबरों का प्रकाशन दैनिक घटती-घटना ने वर्ष 2023 तक लगातार किया था,वही अब जांच और निलंबन आदेशों के रूप में सही साबित होती दिख रही हैं,यह मामला अब केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं,बल्कि सत्ता-प्रभाव,फाइल गायब कराने और आदिवासी अधिकारों पर सुनियोजित चोट का गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया है,खड़गवां एकलव्य आवासीय विद्यालय का यह मामला छत्तीसगढ़ में आदिवासी कल्याण योजनाओं की निगरानी और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है अब वक्त है कि प्रशासन यह साबित करे कि आदिवासी छात्रों के हक पर डाका डालने वालों के लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं है, और ऐसी सख्त नजीर बने कि भविष्य में कोई भी इस तरह की गलती करने की हिम्मत न करे।

स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था भ्रष्टाचार का सिलसिला

एकलव्य आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना आदिवासी बच्चों को बेहतर आवासीय शिक्षा,पौष्टिक भोजन,वस्त्र,शैक्षणिक सामग्री और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी,लेकिन खड़गवां के पोड़ीडीह स्थित इस विद्यालय में स्थापना काल से ही जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों-कर्मचारियों ने इस उद्देश्य को ही कमजोर कर दिया,आरोप है कि छात्रावास,भोजन व्यवस्था,दैनिक उपयोग की सामग्री,रखरखाव और अन्य मदों में शासन से प्राप्त राशि का वर्षों तक दुरुपयोग किया गया। आदिवासी छात्र-छात्राओं की बुनियादी सुविधाओं में लगातार कटौती कर राशि की बंदरबाट की जाती रही।

कोरोना काल में भी नहीं बख्शी गई शासकीय राशि...

सूत्रों और जांच रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना महामारी जैसे संवेदनशील दौर में भी विद्यालय के नाम पर प्राप्त बजट का दुरुपयोग किया गया। जब पूरा देश संकट से जूझ रहा था और आदिवासी परिवार सबसे अधिक प्रभावित थे,उसी समय कुछ जिम्मेदारों ने बच्चों की सुविधाओं पर सेंध लगाकर सरकारी धन का निजी लाभ उठाया,यह भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि अलग-अलग समय पर विद्यालय में विभिन्न प्रभार संभालने वाले कई लोगों की भूमिका इसमें संदिग्ध पाई गई है।

2023 में जांच, दोषी चिन्हित,फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं ?

दैनिक घटती-घटना द्वारा लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद कांग्रेस शासनकाल में ही इस पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू की गई थी। जांच में कई तत्कालीन जिम्मेदार प्रथम दृष्टया दोषी भी पाए गए थे, इसके बावजूद न तो निलंबन हुआ और न ही वसूली या दंडात्मक कार्रवाई, सबसे गंभीर आरोप यह है कि दोषियों को बचाने के लिए सत्ता-शासन के प्रभाव का इस्तेमाल किया गया और पूरी जांच फाइल ही गायब करा दी गई। बताया जाता है कि जिन पर आरोप थे,वे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए थे या उनके परिजन थे,जिसके कारण कार्रवाई को वर्षों तक रोके रखा गया।

फाइल दोबारा सामने आई,अब शुरू हुई कार्रवाई...

लंबे अंतराल के बाद,जब इस मुद्दे को दैनिक घटती घटना ने फिर से प्रमुखता से उठाया,तब प्रशासनिक स्तर पर खोज-पड़ताल तेज हुई। इसके बाद वह जांच फाइल पुनः सामने आई, जिसमें दोषियों की पहचान पहले ही की जा चुकी थी,अब भाजपा शासनकाल में उसी जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। ताजा जानकारी के अनुसार,भ्रष्टाचार में शामिल रहे कई तत्कालीन जिम्मेदार कर्मचारियों के निलंबन आदेश जारी किए जा चुके हैं और आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

बड़ा सवालःक्या निलंबन ही अंतिम कार्रवाई होगी ?

इस पूरे प्रकरण में अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह मामला केवल निलंबन तक ही सीमित रहेगा? क्या दोषी पाए गए कर्मचारियों से शासकीय राशि की वसूली की जाएगी? क्या उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया के तहत विभागीय के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई भी होगी? विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि आदिवासी छात्र-छात्राओं की सुविधाओं में चोरी करना केवल वित्तीय अपराध नहीं,बल्कि सामाजिक अपराध भी है। यदि इस मामले में कड़ी वसूली और दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई,तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कमजोर संदेश देगा।

आदिवासी अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मामला...

यह पूरा प्रकरण आदिवासी समुदाय के अधिकार,शिक्षा और सम्मान से सीधे जुड़ा हुआ है। एकलव्य विद्यालय जैसे संस्थानों में भ्रष्टाचार न केवल बच्चों के वर्तमान को नुकसान पहुंचाता है,बल्कि उनके भविष्य पर भी गहरा असर डालता है,अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस मामले में उदाहरणात्मक कार्रवाई कर पाता है या नहीं, यदि दोषियों को केवल निलंबित कर छोड़ दिया गया,तो यह न्याय नहीं बल्कि आधा-अधूरा फैसला माना जाएगा।

मनेंद्रगढ़ को नए साल का बड़ा तोहफाःमिनी स्टेडियम को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं, 98 लाख की स्वीकृति

-संवाददाता-
मनेन्द्रगढ़,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

नए साल की शुरुआत मनेंद्रगढ़ के खेल प्रेमियों और स्थानीय खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेंद्रगढ़ विधायक श्यामबिहारी जायसवाल की विशेष पहल पर शहर के स्वामी आत्मानंद विद्यालय खेल मैदान में स्थित मिनी स्टेडियम का आधुनिकीकरण किया जाएगा,राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 98 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है, इस राशि से मिनी स्टेडियम में आधुनिक मंच,दर्शकों के लिए गैलरी,खिलाड़ियों के लिए पवेलियन सहित अन्य आवश्यक खेल सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिल सकेगा।

खेल प्रतिभाओं को मंच देने की दिशा में अहम कदम

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 से मनेंद्रगढ़ प्रेसिडेंट क्लब द्वारा आयोजित फ्लड लाइट रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट के कारण हाई स्कूल मैदान को मिनी स्टेडियम का दर्जा मिला था,क्लब और खेल प्रेमियों द्वारा लंबे समय से मैदान के विस्तार और विकास की मांग की जा रही थी, पिछले वर्ष आयोजित फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में प्रेसिडेंट क्लब के अध्यक्ष एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता आशीष सिंह ने मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के समक्ष मैदान के विकास की मांग रखी थी। खेल के प्रति युवाओं के उत्साह को देखते हुए मंत्री ने मंच से ही लगभग एक करोड़ रुपये खर्च कर स्टेडियम के विकास की घोषणा की थी।

घोषणा को अमल में लाने के लिए उठाए गए त्वरित कदम

घोषणा के बाद मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा मिनी स्टेडियम का विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार कर नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा गया। इसके पश्चात मंत्री ने उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को पत्र लिखकर प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिलाने का आग्रह किया। परिणामस्वरूप 98 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

जल्द होगा भूमि पूजन, खेल जगत में उत्साह

मिनी स्टेडियम के विकास को लेकर क्षेत्र के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शीघ्र ही निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा, इस उपलब्धि पर मनेंद्रगढ़ प्रेसिडेंट क्लब के अध्यक्ष अधिवक्ता आशीष सिंह, सुरजीत सिंह रैना,रमणीक सिंह रैना,हरीश गुप्ता,रविकांत सिंह राजपूत,प्रकाश त्रिपाठी,हर्षित गुप्ता एवं भूपेंद्र भंडारकर सहित क्लब के सभी सदस्यों ने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का आभार व्यक्त किया है।

छत्तीसगढ़ शासन,जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, मनेन्द्रगढ़, जिला - एम. सी. बी. (छ.ग.)
ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal: https://eproc.egstate.gov.in
(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 182425 निविदा सूचना क्र. 08/वलेलि/2025-26. दिनांक 29.12.2025

निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 19.01.2026, (17.30 बजे) तक ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है -
कार्य का नाम - मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर जिले के विकासखण्ड - खड़गवां की खड़गवां जलाशय योजना के नहर का जीर्णोद्धार कार्य ।
अनुमानित लागत - रू. 157.91 लाख (जी.एस.टी. छोड़कर)
अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट eProcurement Portal:https://eproc.egstate.gov.in पर दिनांक 05.01.2026, समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड़ किये जा सकते है।

नोट -1.निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.egstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
2. निविदा की अनुमानित लागत एस. ओ. आर. दिनांक 01.05.2025 एवं दिनांक 08.08.2025 के जारी संशोधन के अनुसार है।
3. निविदाकार द्वारा अपने वित्तीय प्रस्ताव में जी.एस.टी.सहित निविदा भरा जाना है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, मनेन्द्रगढ़,
जिला - एम. सी. बी. (छ.ग.)
कृते अधीक्षण अभियंता श्याम बरनई
परियोजना मण्डल, अंबिकापुर (छ.ग.)

जी नंबर-252605770/4

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर -2 जिला- सरगुजा (छ.ग.)

रा0प्र0क0 /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका मोहरमनिया आ0 बोधनराम, निवासी ग्राम कंचनपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदिका के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम कंचनपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 52, 81, 82, 83, 84/2, 85, 101, 113/3, 126, 141/2, 150/2, 151/1, 161, 164/2, 421/1, 549, 568/1, 803, 837 खसरा 19 कुल रकबा 6.710 हे0 आवेदिका सहित कृष्णभान, विजय, त्रिभला, कमलबसिया, निर्मला, चंद्रा पिता चन्द्रभान, प्यारो बेवा चन्द्रभान, महेन्द्र, सहेन्द्र, बृजकुमार आ0 बाबन, बसंती बेवा बाबन के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख ऑनलाईन बी-1 में त्रुटिवश शासकीय पट्टेदार (कृषि) अंकित हो गया है। आवेदिका द्वारा राजस्व अभिलेखों में त्रुटिपूर्वक अंकित शासकीय पट्टेदार (कृषि) को सुधार करते हुए भूमि स्वामी दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जो जांच व प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 21/01/2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 24/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-02

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर -2 जिला- सरगुजा (छ.ग.)

रा0प्र0क0 /अ-63/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बहादुर राम आ. रामकरण व अन्य, निवासी ग्राम रजपुरीखुर्द, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका के स्वत्व आधिपत्य की भूमि ग्राम रजपुरीखुर्द में भूमि कुल खसरा नंबर 389, 351/1, 440/2 कुल खसरा नंबर 03 कुल रकबा 0.506 हे0 स्थित है। आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि इस न्यायालय के रा.प्र.क. 02/अ-27/2013-14 फुलमेत बेवा प्रेमसाय वगैरह प्रति रामलखन वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31/01/2017 के अनुसार खसरा नंबर 540/4 अंकित है जिसे त्रुटि बताते हुए सही रकबा 640/4 दर्ज करने तथा पारित आदेश में मृत पक्षकार प्रेमसाय, फुलमेत, रामकर ण एव रूपसाय के उत्तराधिकारियों के संबंध में सुधारात्मक आदेश पारित हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 12/01/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 15/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन, पदमुद्रा से जारी ।

सील

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-02

एक कार्यालय...दो आदेश

कलेक्टर की सख्ती बनाम कमिश्नर की बहाली

नियम,अधिकार और प्रक्रिया पर खड़े हुए प्रशासनिक सवाल...

निलंबन से बहाली तकः क्या प्रक्रिया से ऊपर कोई आदेश?

गलत कृत्य, सही सवालः निलंबन क्यों नहीं टिक पाया?

कलेक्टर कार्यालय में हड़ताल समर्थनः अनुशासन सही,प्रक्रिया कमजोर

दो दिन में बहाली ने क्या कलेक्टर के अधिकार कमजोर कर दिए?

अधिकार बनाम प्रक्रियाः एमसीबी कलेक्टर कार्यालय प्रकरण की पूरी पड़ताल

जब एक आईएएस दोषी मानता है और दूसरा निर्दोष–प्रशासनिक एकरूपता पर सवाल

क्या है पूरा मामला-

छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठा था। इसी दौरान 30 दिसंबर 2025 को फेडरेशन से जुड़े कुछ कर्मचारी कार्यालयीन समय में एमसीबी कलेक्टर कार्यालय के भीतर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने वहां कार्यरत कर्मचारियों से हड़ताल के समर्थन में शामिल होने का अनुरोध/दबाव बनाया, कलेक्टर ने इसे सरकारी कार्य में बाधा मानते हुए तीन कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर दिया, कलेक्टर की इस कार्रवाई को लेकर उसी दिन से प्रशासनिक और कर्मचारी वर्ग में मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आईं–कुछ ने इसे अनुशासन बनाए रखने की जरूरी कार्रवाई बताया, तो कुछ ने इसे कठोर और जल्दबाजी करार दिया।

-रवि सिंह-

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, 03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल के दौरान एमसीबी कलेक्टर कार्यालय में घटित घटनाक्रम अब केवल तीन कर्मचारियों के निलंबन और बहाली तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह मामला प्रशासनिक अधिकार, प्रक्रिया की अनिवार्यता और आईएएस स्तर पर निर्णयों की एकरूपता पर गंभीर बहस का विषय बन गया है।

बता दे कि यह पूरा मामला न तो केवल कर्मचारियों के हक में है और न ही केवल प्रशासन की सख्ती के खिलाफ। यह मामला है अधिकार बनाम प्रक्रिया का, कर्मचारियों का कार्यालय के भीतर हड़ताल समर्थन करना गलत और अनुचित माना जा सकता है, लेकिन उस गलत कृत्य पर की गई कार्रवाई यदि नियमों और प्रक्रिया के विपरीत हो,तो वह टिक नहीं सकती, इस प्रकरण ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक अनुशासन उतना ही जरूरी है जितनी जरूरी न्यायसंगत और विधिसम्मत प्रक्रिया,अन्यथा, एक आदेश पर दूसरा आदेश भारी पड़ता रहेगा–और सवाल उठते रहेंगे कि आखिर सही कौन?

दो दिन बाद पलटा फैसला...

इस बीच कर्मचारियों ने निलंबन आदेश के खिलाफ आयुक्त, सरगुजा संभाग के न्यायालय में अपील की, 02 जनवरी 2026 को आयुक्त ने दोनों मामलों में (वि.अप.क्र. 02/2026 एवं 03/2026) कलेक्टर द्वारा पारित निलंबन आदेशों को निरस्त करते हुए कर्मचारियों को बहाल कर दिया, यहीं से विवाद और गहरा गया,एक आईएएस अधिकारी के लिए कर्मचारी दोषी, दूसरे आईएएस अधिकारी के लिए वही कर्मचारी दो दिन में निर्दोष?

आयुक्त के आदेश का कानूनी आधार...

आयुक्त के आदेशों का गहन अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि कर्मचारियों के कृत्य को सही ठहराया नहीं गया,बल्कि पूरा जोर प्रक्रियात्मक त्रुटि पर है, आयुक्त ने अपने आदेश में साफ कहाः निलंबन से पहले,न कारण बताओ नोटिस दिया गया,न स्पष्टीकरण का अवसर,न ही सुनवाई का मौका,यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है,दूसरे पक्ष की बात सुने बिना पारित आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता,इसी आधार पर निलंबन आदेशों को रद्द करते हुए कर्मचारियों को पूर्व पदस्थापना पर बहाल किया गया और निलंबन अवधि को कार्यावधि मान्य किया गया।

कलेक्टर के अधिकार पर सवाल या प्रक्रिया की चूक?

यहां सबसे अहम बिंदु यह है कि, कलेक्टर जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है,अपने कार्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने और सरकारी काम में बाधा रोकने का उसे पूरा अधिकार है,लेकिन अधिकार का प्रयोग भी तय प्रक्रिया के भीतर ही होना चाहिए,प्रशासनिक कानून के अनुसार निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई से पहले न्यूनतम प्रक्रिया–नोटिस और सुनवाई–अनिवार्य है। आयुक्त ने कलेक्टर के अधिकारों को नकारा नहीं, बल्कि यह कहा कि अधिकार का प्रयोग नियमों के अनुरूप नहीं हुआ।

धारा 144 का सवाल...

मामले में यह सवाल भी उठा कि क्या कलेक्टर कार्यालय में हर समय धारा 144 लागू रहती है? कानूनी स्थिति स्पष्ट है धारा 144 स्वतः हर समय लागू नहीं रहती,लेकिन कलेक्टर कार्यालय संवेदनशील प्रशासनिक क्षेत्र होता है,जहां बिना अनुमति भीड़, प्रदर्शन या दबाव निषिद्ध माना जाता है,यानी कार्रवाई का आधार धारा 144 नहीं, बल्कि सरकारी कार्य में बाधा होना चाहिए था–पर कार्रवाई प्रक्रियागत रूप से कमजोर रही।

एक आदेश से दूसरा आदेश–भ्रम की स्थिति...

जब एक कलेक्टर का आदेश दो दिन में ही कमिश्नर द्वारा निरस्त हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि आमजन और कर्मचारी वर्ग में यह सवाल उठता है कि, क्या नियम व्यक्ति-विशेष पर निर्भर हो गए हैं? क्या प्रशासनिक निर्णयों में राजनीतिक या बाहरी दबाव की भूमिका है? या फिर नीचे के स्तर पर लिए गए फैसलों में कानूनी सतर्कता की कमी है?

हड़ताल का अधिकार बनाम कार्यालय की मर्यादा या क्या कलेक्टर कार्यालय में घुसकर काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर लाना जायज़ था...

छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल के दौरान एमसीबी कलेक्टर कार्यालय में जो दृश्य सामने आया, उसने केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि संवैधानिक और नैतिक बहस को जन्म दे दिया है। सवाल यह नहीं है कि कर्मचारियों की मांग जायज़ थी या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि मांग रखने और आंदोलन का तरीका कितना वैधानिक था।

लेकिन सवाल फिर भी बचता है...

क्या गलत तरीका अपनाने वालों को सिर्फ प्रक्रिया की कमी के कारण तुरंत राहत मिल जानी चाहिए?

क्या इससे भविष्य में यह संदेश नहीं जाता कि पहले दबाव बनाओ,बाद में कानून देख लिया जाएगा?

क्या दो दिन में बहाली ने कलेक्टर की वैधानिक को कमजोर नहीं किया?

सही कौन, गलत कौन?:-

कर्मचारियों की मांग रखना लोकतांत्रिक अधिकार है...

कलेक्टर कार्यालय में घुसकर काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर लाने का प्रयास असंवैधानिक और अनुचित है...

कलेक्टर का हस्तक्षेप प्रशासनिक रूप से सही था...

लेकिन कार्रवाई की प्रक्रिया कानूनी रूप से कमजोर थी...

कमिश्नर का आदेश कानून सम्मत है पर उसकी तत्कालता और संदेश पर सवाल बने रहेंगे...

संविधान क्या कहता है हड़ताल को लेकर?

भारतीय संविधानः अनुच्छेद 19(1)(c) संघ बनाने और सामूहिक गतिविधि का अधिकार देता है, लेकिन हड़ताल को मौलिक अधिकार नहीं मानता,सुप्रीम कोर्ट की बार-बार की गई व्याख्या के अनुसार सरकारी कर्मचारी को हड़ताल का अधिकार सीमित है और वह भी सार्वजनिक व्यवस्था, कार्यालयीय अनुशासन और प्रशासनिक कार्य में बाधा न डालने की शर्त पर।

हड़ताल के स्थापित नियम क्या कहते हैं?

प्रशासनिक नियमों और सेवा आचरण के अनुसार हड़ताल करने वाले कर्मचारी कार्यालय समय के बाहर, कार्यालय परिसर के बाहर, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन वेः कार्यालय के अंदर प्रवेश कर, काम कर रहे कर्मचारियों को कार्यस्थल से बाहर लाने या काम रोकने का अधिकार नहीं रखते।

महत्वपूर्ण कानूनी अंतर (जो अक्सर भ्रमित करता है)...

हड़ताल से जुड़े नियम यह मानते हैं कि यदि कर्मचारी हड़ताल को सफल बनाना चाहते हैं, तो वे कार्यस्थल पर जाने से पहले, घर पर, रास्ते में, व्यक्तिगत रूप से, निवेदन कर सकते हैं, जबरदस्ती, दबाव या बाधा पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन एक बार जब कोई कर्मचारी कार्यस्थल पर पहुँच गया, तो उसे वहां से हटाने का कोई अधिकार हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को नहीं है।

यहीं से एमसीबी का मामला अलग हो जाता है...

एमसीबी में आरोप यह नहीं है कि कर्मचारियों से सहयोग मांगा गया आरोप यह है कि कलेक्टर की अनुमति के बिना कलेक्टर कार्यालय के भीतर, कार्यालयीन समय में काम कर रहे कर्मचारियों को ÷निवेदन÷ के नाम पर बाहर लाने का प्रयास किया गया, यह सीधे-सीधे कार्यालयीय मर्यादा का उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधा, प्रशासनिक अनुशासन को चुनौती की श्रेणी में आता है।

तो क्या कलेक्टर की कार्रवाई गलत थी?

नैतिक और प्रशासनिक दृष्टि से–नहीं,कलेक्टरः जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है, अपने कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने का अधिकार रखता है, बिना अनुमति प्रवेश और कार्य में बाधा पर,तत्काल हस्तक्षेप कर सकता है, इस बिंदु पर कलेक्टर की आपत्ति और हस्तक्षेप पूरी तरह जायज़ था।

फिर गलती कहाँ हुई?

गलती कार्रवाई के तरीके में हुई,प्रशासनिक कानून कहता हैः निलंबन से पहले नोटिस,स्पष्टीकरण,सुनवाई,अनिवार्य है (जब तक अत्यधिक आपात स्थिति न हो)। कलेक्टर नेः अनुशासनात्मक चिंता सही पहचानी, लेकिन सीधे निलंबन कर दिया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ।

कमिश्नर ने दो दिन में बहाली क्यों की?

यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, कमिश्नर ने यह नहीं कहा कि कर्मचारियों का कृत्य सही था या कार्यालय में घुसना जायज़ था कमिश्नर ने सिर्फ यह कहा कि गलत कृत्य पर भी कार्रवाई सही प्रक्रिया से होनी चाहिए,इसी कारण निलंबन आदेश रद्द किया गया,बहाली की गई,क्योंकि आदेश कानूनी प्रक्रिया में कमजोर था।

प्रशासनिक कार्रवाई पर ब्रेकःएमसीबी में निलंबन निरस्त, कर्मचारी बहाल

तहसील भैयाथान का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण,नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई को लेकर दिया दिशा-निर्देश

-संवाददाता-

सूरजपुर,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर एस. जयवर्धन ने शनिवार को तहसील भैयाथान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

भटगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-05 अंतर्गत तहसील भैयाथान में कुल 44 नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया गया था। इनमें से 25 मतदाताओं की सुनवाई पूर्ण कर ली गई है, जबकि शेष मतदाताओं की सुनवाई के लिए 05 जनवरी 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (ब्लूह) भी उपस्थित रहे, सुनवाई के दौरान प्राप्त दस्तावेजों को परीक्षण हेतु संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नो-मैपिंग मतदाताओं से जुड़े मामलों का शीघ्र एवं नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की भी समीक्षा की और उपस्थित अधिकारियों को सभी कार्य समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

क्या था पूरा मामला...

30 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल के दौरान कुछ कर्मचारी कार्यालयीन समय में एमसीबी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने वहां कार्यरत कर्मचारियों से हड़ताल के समर्थन में शामिल होने का अनुरोध किया। इसे सरकारी कार्य में बाधा मानते हुए कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने तीन कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर दिया था,इस कार्रवाई को लेकर कर्मचारी संगठनों और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी।

प्रशासनिक बहस तेज...

इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अनुशासन बनाए रखने की कार्रवाई प्रक्रिया से ऊपर हो सकती है? क्या जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले प्रशासनिक अधिकारों को कमजोर करते हैं? और क्या एक आदेश के तुरंत बाद दूसरे आदेश से प्रशासनिक भ्रम की स्थिति बनती है? एमसीबी जिले की यह घटना अब केवल स्थानीय मामला नहीं रह गई है, बल्कि राज्य स्तर पर प्रशासनिक अनुशासन और विधिसम्मत प्रक्रिया के संतुलन की एक अहम मिसाल के रूप में देखी जा रही है।

-संवाददाता-

एमसीबी,03 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल के दौरान मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में कलेक्टर कार्यालय से जुड़ा विवाद अब एक अहम प्रशासनिक मोड़ पर पहुंच गया है। हड़ताल के दौरान कार्यालय परिसर में कथित रूप से समर्थन मांगने के आरोप में निलंबित किए गए तीन शासकीय कर्मचारियों का निलंबन सरगुजा संभाग आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया गया है,साथ ही तीनों कर्मचारियों को उनके पूर्व पदस्थापना स्थान पर बहाल करने के आदेश भी जारी किए गए हैं,आयुक्त के आदेश के बाद यह मामला केवल कर्मचारियों की बहाली तक सीमित नहीं रहा,बल्कि प्रशासनिक अधिकार,प्रक्रिया और अनुशासन को लेकर व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।

आयुक्त के आदेश में क्या कहा गया...

सरगुजा संभाग आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि निलंबन से पूर्व न तो कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया, न ही स्पष्टीकरण या सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया,यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है,इसी आधार पर निलंबन आदेशों को निरस्त करते हुए कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश दिए गए, आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश में कर्मचारियों के कृत्य को सही नहीं ठहराया गया है,बल्कि कार्रवाई की प्रक्रियागत त्रुटि को आधार बनाया गया है।

गुलाब कमरो का तीखा बयान...

पूर्व विधायक एवं छत्तीसगढ़ ट्रेड यूनियन काउंसिल के प्रांताध्यक्ष गुलाब कमरो ने निलंबन निरस्त होने को सत्य,संविधान और कर्मचारी एकता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई शुरू से ही एकपक्षीय, द्वेषपूर्ण और नियमविरुद्ध थी,गुलाब कमरो ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई करने वाला प्रशासन भ्रष्टाचार के मामलों में आंख मूंदे बैठा रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस पूरे मामले में मुख्य सचिव से कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।

कर्मचारियों ने जताया आभार...

निलंबन निरस्त होने के बाद कर्मचारी प्रतिनिधि शंकर सुमन मिश्र, गोपाल सिंह,प्रेमचंद गुप्ता,गोपाल बुनकर और संजय पांडे ने गुलाब कमरो से मुलाकात कर उनके समर्थन के लिए आभार जताया। इस अवसर पर गुलाब कमरो ने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई में वे हमेशा साथ खड़े रहेंगे।

CMYK

फिर नायक बनकर आएंगे अनिल कपूर? सुपरहिट फिल्म का आ सकता है दूसरा पार्ट

अनिल कपूर ने अपने शानदार करियर में कई यादगार और बड़ी हिट फिल्में दी हैं और उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है नायक। यह राजनीतिक ड्रामा आज भी दर्शकों का दिल जीत रहा है और प्रशंसक 2001 में आई इस फिल्म के सीक्वल की मांग कर रहे हैं। अब एक खबर आई है कि अनिल कपूर ने फिल्म के अधिकार खरीद लिए हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार,सनम तेरी कसम (2016) के निर्माता दीपक मुकुट के पास नायक के अधिकार थे। बताया जा रहा है कि अनिल कपूर ने उनसे ये अधिकार खरीद लिए हैं। वे इन अधिकारों को अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है। साथ ही,वे इसका सीक्वल बनाना चाहते हैं। वे इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि वर्षों से इस फिल्म को कितना प्यार मिला है और उनका मानना है कि नायक की कहानी में दूसरे भाग की अपार संभावनाएं हैं।

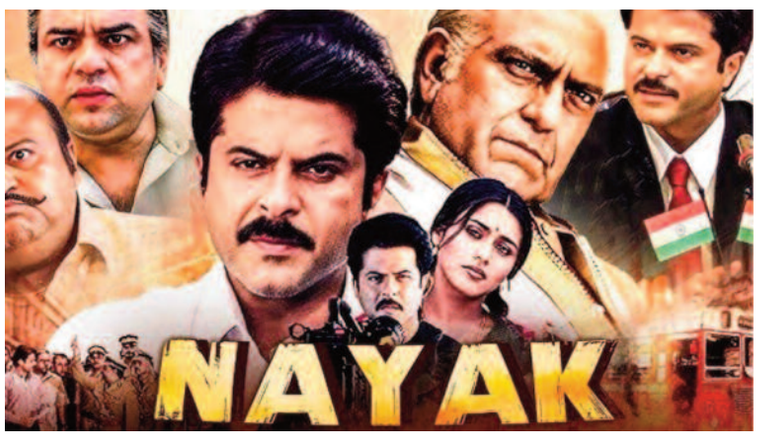

सुपरहिट रही थी फिल्म नायक

इससे पहले पोर्टल से बात करते हुए दीपक ने बताया था कि मैंने नायक के निर्माता श्री ए. एस. रत्नम से इसके अधिकार प्राप्त किए थे। मेरे पास उनकी अन्य फिल्मों जैसे तेजस्विनी (1994), दिल ही दिल में (1999) आदि के नेगेटिव राइट्स भी हैं। ये अधिकार मैंने 10 साल पहले हासिल किए थे। अनिल कपूर, रानी मुखर्जी और अमरीश पुरी की राजनीतिक फिल्म नायक- द रियल हीरो 7 सितंबर, 2001 को रिलीज हुई थी। एस. शंकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनकी 1999 की तमिल फिल्म मुधलवन का रीमेक थी। नायक ने हाल ही में 24 साल पूरे किए हैं। फिल्म की 24वीं वर्षगांठ के अवसर पर, अनिल कपूर ने अपने नवीनतम इंस्टाग्राम पोस्ट में नायक फिल्म की कई तस्वीरें साझा कीं।

अनिल कपूर ने याद की थी फिल्म

कैप्शन में अनिल कपूर ने लिखा था कि कुछ भूमिकाएं आपको परिभाषित करती हैं। नायक उनमें से एक थी। पहले यह भूमिका आमिर और शाहरुख को दी गई थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इस किरदार को जीना है- और मैं शंकर सर का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मंच पर शाहरुख के ये शब्द मुझे हमेशा याद रहेंगे, यह भूमिका अनिल के लिए बनी थी। ऐसे पल हमेशा के लिए यादगार रहते हैं। शाहरुख खान 2001 में नायक के ऑडियो रिलीज़ पार्टी में मौजूद थे। उन्होंने फिल्म के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए कार्यक्रम में शिरकत की थी। कार्यक्रम में शाहरुख ने कहा कि मैं शूटिंग छोड़कर यहां आया हूं। दो कारणों से। एक तो इसलिए कि मेरा एक बहुत करीबी दोस्त इसमें अभिनय कर रहा है- अनिल कपूर। और बेशक,रानी भी वहां हैं। और मैं उन्हें बधाई देने आया हूं।

विजय देवरकोंडा की किंगडम 2 नहीं बनेगी

पहले पार्ट के फ्लॉप होने के बाद प्रोड्यूसर ने बदला फैसला, अब डायरेक्टर के साथ दूसरी फिल्म की तैयारी

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इन दिनों पर्सनल लाइफ और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में छाए हैं। उनकी फिल्मों के अपडेट्स फैंस को बांधे रखते हैं, लेकिन अब एक झटका लगा है। विजय देवरकोंडा की बहुचर्चित फिल्म 'किंगडम 2' अब कभी नहीं बनेगी। फिल्म के प्रोड्यूसर नागा वामसी ने इस फिल्म के पहले पार्ट के फ्लॉप होने के बाद यह फैसला लिया है।किंगडम 2025 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। गौतम तिन्नानुरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विजय देवरकोंडा और भाग्यश्री बोरसे का अहम रोल था। फैंस को पिछले कुछ समय से फिल्म के सीक्वल का इंतजार था, लेकिन मेकर्स ने प्लान कैंसल कर दिया।

प्रोड्यूसर नागा वामसी ने इंटरव्यू में साफ कहा कि अब वो फिल्म नहीं बना रहे। जब पूछा गया कि क्या फिल्म को एक पार्ट में खत्म करना बेहतर होता बजाय सीक्वल प्लान के, तो उन्होंने जवाब दिया कि पिछली बातों पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। इससे सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर गौतम तिन्नानुरी को तकलीफ होगी। अब कुछ करने को बचा नहीं है।

नागा वामसी ने भविष्य की प्लानिंग पर बात करते हुए कहा कि जल्द ही वो डायरेक्टर गौतम तिन्नानुरी के साथ एक नई फिल्म कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गौतम तिन्नानुरी एक अलग जॉनर की फिल्म डेवलप कर रहे हैं।

विजय देवरकोंडा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो लंबे समय रश्मिका मंदाना के साथ डेटिंग, सगाई की खबरों से सुर्खियों में हैं। नई रिपोर्ट्स के माने तो अब रश्मिका और विजय 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर में सात फेरे लेने जा रहे हैं। इस दौरान दोनों की फैमिली और करीबी दोस्त मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस प्राइवेट शादी के लिए तैयारियां चल रही हैं।

इक्कीस और बॉर्डर 2 के बाद एक और देशभक्ति फिल्म का ऐलान, जारी हुआ फर्स्ट लुक पोस्टर

सिनेमाघरों में हाल ही में एक वॉर ड्रामा ने दस्तक दी है,जिसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा स्टारर इक्कीस की, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र मुख्य भूमका में हैं। ये फिल्म नए साल के मौके पर 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अब जल्दी ही एक और वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 भी दर्शकों के बीच दस्तक के लिए तैयार है। इन दमदार फिल्मों के बीच एक और वॉर ड्रामा का ऐलान हो चुका है। हम बात कर रहे हैं इंडिया-पाकिस्तानः द फाइनल रेजोल्यूशन की, जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर जारी करते हुए मेकर्स ने इसका ऐलान किया है।

इंडिया-पाकिस्तानः द फाइनल रेजोल्यूशन का हुआ ऐलान

फिल्ममेकर युवराज कुमार ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'इंडिया पाकिस्तान : द फाइनल रेजोल्यूशन' का ऐलान किया है, जो भारत-पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को रिसर्च बेस्ड सिनेमाई दृष्टिकोण के साथ बनाई गई है। फिल्म की कहानी कश्मीर के इर्द-गिर्द घूमती है और इसका फोकस कश्मीर को शांति की शुरुआत बनने दें÷ पर है, जिसके फर्स्ट लुक पोस्टर ने ही दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है।

अनसुलझे संघर्ष पर आधारित है फिल्म

मेकर्स के अनुसार फिल्म दशकों से चले आ रहे अनसुलझे संघर्ष की वास्तविकताओं और इसके रिजल्ट की पड़ताल करती है। खासतौर पर सीमा के दोनों ओर रहने वाले आम नागरिकों पर इसके प्रभाव को दिखाती है। फिल्म की कहानी किसी विचारधारा पर नहीं बल्कि मानवीय पहलुओं पर आधारित है। मेकर्स का कहाना है कि फिल्म विभाजन के बजाय संवाद और आत्ममंथन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

कौन हैं कृति सैनन के होने वाले जीजा जी? डायमंड रिंग दिखाते हुए शेयर की खुशखबरी,

कुणाल खेमू की रह चुकीं हीरोइन

अभिनेत्री और कृति सैनन की बहन नूपुर सैनन ने अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड और गायक स्टेबिन बेन से सगाई कर ली है। अपने इंस्टाग्राम पर प्रपोज़ल की कुछ झलकियां साझा करते हुए नूपुर ने लिखा, संभावनाओं से भरी दुनिया में, मुझे अब तक का सबसे आसान हां कहने का मौका मिला, इसके बाद उन्होंने लाल दिल और बुरी नजर वाले इमोजी लगाए। पोस्ट की मुख्य तस्वीर में स्टेबिन घुटनों के बल बैठकर प्यार से नूपुर का हाथ पकड़े हुए हैं। पृष्ठभूमि में क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिखे हुए पोस्टर लिए लोग भी दिख रहे हैं। नवविवाहित जोड़ा एक झील के बीच में, मनमोहक नज़ारों के बीच नजर आया।

पेरेंट्स के साथ भी की बातचीत

अपने माता-पिता के साथ इस खास पल को साझा करते हुए, नूपुर और स्टेबिन ने प्रपोजल के बाद वीडियो कॉल पर भी उनसे बात की। खूबसूरत फूलों वाली ड्रेस में सजी नूपुर ने अपनी बड़ी सगाई की अंगूठी भी दिखाई। स्टेबिन ने इस खास मौके के लिए नीले रंग के फॉर्मल कपड़े पहने थे। एक तस्वीर में एक महिला इस खुशहाल जोड़े को गले लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन संभवतः यह कृति हैं जो इस जोड़े के लिए अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। पिछले एक महीने से अटकलें लगाई जा रही थीं कि नूपुर और स्टेबिन जल्द ही उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालिया खबरों के अनुसार, उनकी शादी अगले हफ्ते फेयरमोंट उदयपुर पैलेस में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में होने वाली है। बताया जा रहा है कि यह जोड़ा 2023 से एक-दूसरे को डेट कर रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

कौन हैं कृति सैनन के जीजा जी?

भोपाल में जन्मे और पले-बढ़े स्टेबिन बेन को बचपन से ही संगीत से प्यार हो गया था। प्रस्तुति से उनका पहला परिचय स्कूल में हुआ, जहां उन्हें एहसास हुआ कि गाना सिर्फ एक शौक से कहीं बढ़कर है। कॉलेज के उत्सवों और स्थानीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। 2016 में, स्टेबिन ने संगीत में पूर्णकालिक करियर बनाने के लिए मुंबई का रुख किया। कई नवागंतुकों की तरह, शुरुआती दिन उनके लिए बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं थे। उन्होंने शहर भर के कैफे और क्लबों में प्रदर्शन किया, छोटे-मोटे कार्यक्रमों पर निर्भर रहते हुए पहचान बनाने की कोशिश की। वह सफलता तब मिली जब उनके द्वारा गाए गए गीत मेरा दिल भी कितना पागल है का कवर ऑनलाइन वायरल हो गया। इस लोकप्रियता ने उन्हें ज़ी म्यूज़िक के साथ अपना पहला बड़ा ब्रेक दिलाने में मदद की, जिससे उद्योग में उनकी निरंतर प्रगति की नींव पड़ी।

कुणाल खेमू के साथ किया काम

नुपुर सैनन भी अपनी बहन कृति सैनन की तरह बॉलीवुड में हीरोइन बनने की जुगत में जुटी हैं। बीते दिनों कुणाल खेमू के साथ नुपुर की सीरीज पॉप कौन में भी उनकी काफी तारीफ हुई थी। हालांकि ये सीरीज ज्यादा लोगों तक पहुंचने में असफल रही थी। लेकिन इसके बाद भी नुपुर ने इस सीरीज में अपने किरदार से काफी तारीफें बटोरी थीं। अब नुपुर भी बॉलीवुड हीरोइन बनने की मशक्कत कर रही हैं।

300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले आशीष विद्यार्थी का एक्सीडेंट

300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर आशीष विद्यार्थी बीती रात एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। आशीष और उनकी पत्नी रूपाली बरुआ का ये एक्सीडेंट गुवाहाटी में हुआ। दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगी. एक्टर ने अब इस बारे में बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात देर रात सड़क हादसे में उन्हें चोट लगी थी और अब वो ठीक हैं. आशीष विद्यार्थी ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि जब वो अपनी पत्नी रूपाली के साथ सड़क पार कर रहे थे,तभी एक बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और अब दोनों एकदम सेफ हैं. उनकी इस खबर से फैंस ने राहत की सांस ली है।

खेल समाचार

एएफआई जनवरी में क्वाली फिकेशन स्टैंडर्ड की घोषणा करेगा

नई दिल्ली,03 जनवरी 2026। जापान में होने वाले एशियन गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड में कुल मेडलों की संख्या को बेहतर बनाने के मकसद से एएफआई (एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) ने शनिवार को क्वालिफिकेशन मार्क की घोषणा की। एएफआई की एक रिलीज़ के अनुसार, एशियन गेम्स के क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड की घोषणा करते हुए, एएफआई के पूर्व अध्यक्ष और प्रवक्ता आदिल सुमरिवाला ने कहा कि एथलीटों के पास सही समय पर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और 2026 सीज़न की बड़ी इंटरनेशनल मल्टी-डिसिप्लिन प्रतियोगिता के लिए टिकट पक्का करने का काफी समय है।

सुमरिवाला ने आगे कहा, एएफआई हर इवेंट में कम से कम दो योग्य एथलीटों का चयन करेगा। एएफआई सिलेक्शन पैनल एशियन गेम्स के लिए भारतीय एथलेटिक्स दल की ताकत पर अंतिम फैसला लेगा। सुमरिवाला, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्षों में से एक हैं, ने कहा कि एथलीटों के मुख्य ग्रुप ने 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया, जो 2026 सीज़न के लिए अच्छा संकेत है। सुमरिवाला ने आगे कहा, चीन में हुए 2022 के पिछले एशियन गेम्स में भारतीय एथलेटिक्स दल ने 29 मेडल जीते थे, जिनमें से छह गोल्ड थे।÷ मुझे विश्वास है कि जापान में होने वाले एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में कुल मेडलों की संख्या बेहतर होगी। सुमरिवाला ने कहा कि चीन में हुए पिछले एशियन गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में छठा स्थान 2026 के एशियन गेम्स के लिए बेंचमार्क था। हालांकि, 200एम, 400एम, 800एमऔर हाई हर्डल्स सहित कई इवेंट्स में, क्वालिफिकेशन मार्क पांचवां स्थान रहा है। एएफआई प्रवक्ता ने कहा,सरकार (खेल मंत्रालय) को एएफआई क्वालिफिकेशन मार्क के बारे में बता दिया गया है। सुमरिवाला ने आगे कहा कि रेस वॉक और मैराथन जैसे इवेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन मार्क जल्द ही एएफआई द्वारा तय किया जाएगा। घरेलू कैलेंडर 24 जनवरी को नेशनल क्रॉस-कंट्री चैंपियनशिप के साथ शुरू होगा, लेकिन पहला बड़ा ट्रैक-एंड-फील्ड इवेंट नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 22 से 25 मई तक भुवनेश्वर में होगी।

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान

» गिल कप्तान,श्रेयस और सिराज की वापसी;
» बुमराह-हार्दिक को रेस्ट,
» पहला मैच 11 जनवरी को

नई दिल्ली,03 जनवरी 2026। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शनिवार को जारी टीम में कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है। अय्यर बीसीसीआई की मेडिकल टीम से फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद ही खेल सकेंगे।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपनी जगह बरकरार रखी है। जबकि ईशान किशन को मौका नहीं मिला है। पेसर जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को बड़ौदा में खेला जाएगा।

जायसवाल बैकअप ओपनर होंगे

यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर बनाया गया है। जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की थी। उन्होंने तीसरे वनडे में नाबाद 116 रन की पारी खेली थी।

मोहम्मद सिराज की वापसी, शमी को जगह नहीं

टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है। उनके साथ अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा टीम के 3 और फ्रंट लाइन पेसर होंगे। वहीं, नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पंड्या की जगह पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स होंगे। पंड्या को भी बुमराह के साथ आराम दिया गया है। साथ ही मोहम्मद शमी को फिर से स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया है।

11 से 18 जनवरी तक 3 वनडे खेलेगा भारत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे की सीरीज 11 से 18 जनवरी तक खेली जाएगी। वडोदरा, राजकोट और इंदौर में तीनों मुकाबले खेले जाएंगे। सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम 3 या 4 जनवरी को रिलीज हो सकती है। हालांकि बीसीसीआई ने टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान पहले ही कर दिया है। 5 टी-20 मैच 21 से 31 जनवरी तक खेले जाएंगे।

भारत की टीम

शुभमन गिल (कप्तान),रोहित शर्मा, विराट कोहली,केएल राहुल (विकेटकीपर),श्रेयस अय्यर (उपकप्तान),वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा,मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा,प्रसिद्ध कृष्णा,कुलदीप यादव,ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी,अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल। श्रेयस अय्यर की उपलब्धता फिटनेस क्लियरेंस पर है।

हरियाणा और गुजरात को भी मिली अहम जीत

विजय हजारे ट्रॉफी रोमांचक

बेंगलुरु,03 जनवरी 2026। शनिवार को बेंगलुरु के पास अलूर क्रिकेट स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप डी मैच में सम्मर गज्जर ने 135 गेंदों पर शानदार 147 रन बनाए, जिससे सौराष्ट्र ने रेलवे को 31 रनों से हरा दिया। गज्जर की पारी में 14 चौके और चार छक्के शामिल थे, जिससे सौराष्ट्र ने 294/8 का स्कोर बनाया, जबकि रेलवे ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। हेत्विक कोटक ने 37 रन और प्रेरक मांकड़ ने 28 रन का योगदान दिया। रेलवे के लिए तेज गेंदबाज कुणाल यादव और जेड.ए. खान ने तीन-तीन विकेट लिए। जवाब में, रेलवे 49.1 ओवर में 263 रन पर ऑल आउट हो गई, हालांकि उपेंद्र यादव ने 97 गेंदों पर 86 रन और आशुतोष शर्मा ने 45 गेंदों पर तेज 65 रन बनाए, जिसमें छह चौके और तीन छक्के शामिल थे। सौराष्ट्र के लिए अंकुर पंवार और मांकड़ ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि ऑलराउंडर चिराग जानी ने दो विकेट लिए। गज्जर को उनकी मैच जिताने वाली पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया ।

एसजी पाइपर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 3-1 से हराया

रांची,03 जनवरी 2026। एक रिलीज़ के अनुसार,एसजी पाइपर्स ने यहां मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में अपने महिला हॉकी इंडिया लीग मुकाबले में जेएसडब्ल्य सूरमा हॉकी क्लब को 3-1 से हराकर एक संयमित और दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने लगातार आक्रामक दबाव और मजबूत बचाव का तालमेल बिठाकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर अपनी जगह बनाए रखी। पाइपर्स के लिए, लोला रिएरा (13%),ज्योति सिंह (18%), और सुनेलिता टोप्पो (58%) ने एक-एक गोल किया,जबकि सूरमा के लिए पेनी स्क्रिब (12%) ने एकमात्र गोल किया। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली,एसजी पाइपर्स और जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब दोनों ने शुरुआती हमले किए और एक-दूसरे को हाई-टेम्पो शुरुआत में परखा। जेएसडब्ल्यू सूरमा ने पहले गोल किया जब पेनी स्क्रिब (12%) ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। स्त्र पाइपर्स ने तुरंत जवाब दिया, अपना आक्रामक दबाव बनाए रखा और लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। उनकी कोशिश आखिरकार पांचवें प्रयास में रंग लाई, जब लोला रिएरा (13%) ने इसे गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया, और पहला क्वार्टर 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ।

छत्तीसगढ़ में 14 नक्सली ढेर...

20 नक्सलियों ने किया सरेंडर

सुकमा में 12, बीजापुर में 2 मारे गए सभी के शव-हथियार बरामद...

बीजापुर,03 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ में शनिवार सुबह दो अलग-अलग जगहों पर मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया है। सुकमा के किस्टाराम इलाके में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए हैं। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और दोनों ओर से रुक-रुककर फायरिंग हो रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर देवा बारसे ने हैदराबाद में सरेंडर कर दिया है। देवा के साथ 20 नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। हैदराबाद में दोपहर 3 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देगी। देवा अपने साथियों के साथ तेलंगाना के मुलुगु पहुंचा था, जहां से पुलिस उसे हैदराबाद लेकर पहुंची थी।

सुकमा-बीजापुर में 14 नक्सली ढेर

सुकमा के किस्टाराम इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी के इनपुट पर डीआरजी की टीम को ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया था। इस दौरान शनिवार सुबह करीब 8 बजे नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में फोर्स ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। सर्चिंग जारी है। इधर, बीजापुर में माओवादियों की मौजूदगी की इनपुट मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने अभियान शुरू किया। डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) की टीम नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान शनिवार तड़के नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुबह करीब 5 बजे से माओवादियों के साथ रुक-रुककर मुठभेड़ चल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से अब तक दो नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी जितेंद्र यादव ने की है। मारा गया एक नक्सली एरिया कमेटी मेंबर है, जिस पर पर 5 लाख का नाम इनाम था, जबकि दूसरा 8 लाख का इनामी था।

नक्सली कमांडर देवा के समर्पण पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान, कहा- यह अच्छा संकेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ने लगातार बनाया था दबाव...

नक्सली कमांडर बारसे देवा के समर्पण पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि छत्तीसगढ़ में पुनर्वास हो, लेकिन तेलंगाना में हो रहा है, यह भी ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। अब मन परिवर्तन के बाद आज वह औपचारिक रूप से सरेंडर करेगा। सब कुछ मार्च 26 के लक्ष्य के तहत हो रहा है।

माओवादी नेटवर्क तेजी से ढह रहा... छत्तीसगढ़ से,सीएम साय ने फोर्स को दी बधाई

बस्तर रेंज के बीजापुर और सुकमा जिलों में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने निर्णायक सफलता हासिल करते हुए 14 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। सीएम साय ने कहा, सुरक्षाबलों की सटीक रणनीति,सतत दबाव और मजबूत जमीनी पकड़ के चलते यहाँ माओवादी नेटवर्क तेजी से ढह रहा है। बस्तर अब भरोसे, विकास और सुरक्षा के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व, सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता, सरकार की संवेदनशील पुनर्वास नीति और जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। हमारी सरकार का संदेश स्पष्ट है- जो अब भी हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं, वे आत्मसमर्पण करें, पुनर्वास नीति अपनाएँ और सम्मान के साथ मुख्यधारा में लौटें।

8 दिन पहले 1 करोड़ का इनामी नक्सली लीडर गणेश ढेर...

इससे पहले 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में 6 नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबरगणेश उईके (69) भी शामिल है। दो महिला नक्सली भी मारी गईं। मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए थे।

शराब घोटाला केस...170 दिन बाद चैतन्य बघेल जेल से रिहा

रायपुर,03 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से करीब 170 दिन बाद रिहा हो गए हैं। जेल के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। चैतन्य के स्वागत के लिए ढोल-नगाड़े बजाए जा रहे हैं। चैतन्य की रिहाई से पहले भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 18 जुलाई को चैतन्य को उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया था।

पोते के जन्मदिन पर उसकी रिहाई हो रही है। भूपेश बघेल अपने बेटे को लेने के लिए पहुंचे हैं। प्रवर्तन निदेशालय और छत्तीसगढ़ एंटी-करप्शन ब्यूरो की ओर से दर्ज केसों में मिली है। प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य को पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार

किया था, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में सितंबर में एसीबी ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब वे पहले से ही जेल में थे। जांच एजेंसियों के अनुसार यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि चैतन्य बघेल इस पूरे शराब सिंडिकेट के संरक्षक थे। उन्होंने करीब 1,000 करोड़ रुपए का लेन-देन व्यक्तिगत रूप से संभाला। इसके अलावा एसीबी का दावा है कि चैतन्य बघेल को हिस्से के तौर पर 200 से 250 करोड़ रुपए मिले और इस पूरे घोटाले की कुल रकम 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है।

छत्तीसगढ़ में आरआई प्रमोशन एग्जाम निरस्त..

प्रश्नपत्र लीक किए,फेल पटवारी को पास किया,रिश्तेदारों को साथ बैठाया

रायपुर,03 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने अपने अहम फैसले में रेवेन्यू इंस्पेक्टर पदोन्नति परीक्षा की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। साथ ही राज्य शासन को नए सिरे से प्रमोशन एग्जाम लेने की छूट दी है। कोर्ट ने माना है कि पदोन्नति परीक्षा में अनियमितता बरती गई, जिसके कारण प्रमोशन की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। इस स्थिति में पूरी प्रक्रिया को वैध नहीं माना जा सकता। बता दें कि पटवारी से आरआई प्रमोशन की लिखित परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। इसमें 2600 से अधिक पटवारी शामिल हुए। 29 फरवरी 2024 को जारी परिणाम में 216 कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया,लेकिन बाद में केवल 13 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया। इसके बावजूद 22 लोगों को नियुक्ति दे दी गई,जिसके बाद विवाद शुरू हुआ।

प्रमोशन एग्जाम के खिलाफ याचिका

जब प्रमोशन एग्जाम में गड़बड़ी सामने आई, तो प्रमोशन से रह गए पटवारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में एग्जाम की प्रक्रिया को गलत और अनुचित बताया गया।

घोटाले पर एसीबी ने दर्ज की है एफआईआर

आरआई प्रमोशन घोटाला सामने आने के बाद पटवारी संघ और शासन के पत्र के आधार पर ईओडब्ल्यू ने 10 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें से दो को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जबकि, 8 की गिरफ्तारी अभी बाकी है। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस मामले में 18 से अधिक लोगों की संलिप्तता पाई गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि परीक्षा में शामिल उन पटवारियों पर भी कार्रवाई प्रस्तावित है, जिन्हें कथित अनियमितता के जरिए प्रमोशन दिया गया। एक मामले में फेल हुए पटवारी को बाद में पास कर दिया। इसी तरह, पति-पत्नी और कुछ जगह भाइयों को साथ बैठाया गया। एजेंसी का दावा है कि प्रमोशन परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही लीक किए गए थे। पटवारियों को पास करने के लिए रिश्तेदारों को एक ही परीक्षा केंद्र में लाइन से बैठाया गया। यही कारण है कि कई कैंडिडेट्स को एक समान अंक मिले। जांच के दौरान एजेंसी को दस्तावेज के साथ तकनीकी सबूत भी मिले हैं।

पटवारियों का आरोप है कि कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को भी प्रमोशन के लिए शामिल किया गया, जिससे योग्य उम्मीदवार प्रमोशन से रह गए। याचिकाकर्ताओं ने इस एग्जाम को रद्द करने की मांग की है।

हाईकोर्ट ने पदोन्नति परीक्षा निरस्त किया

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद आरआई पदोन्नति परीक्षा को निष्पक्षता के अभाव में निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और पक्षपात के संकेत मिलने की बात कही है। हाईकोर्ट ने प्रमोशन और एग्जाम की प्रक्रिया पर कड़ी टिप्पणी की है। इस फैसले के बाद 216 पटवारियों को दी गई पदोन्नति निरस्त हो जाएगी। जस्टिस एनके व्यास ने अपने फैसले में कहा है कि पदोन्नति परीक्षा प्रणाली दूषित थी और चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं थी। कोर्ट ने माना कि परीक्षा और चयन प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता पर सवाल खड़े होते हैं।

घाटे से जूझ रहे पॉवर कंपनी ने 24% टैरिफ बढ़ाने का दिया प्रस्ताव फिर महंगी हो सकती है बिजली

रायपुर,03 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने नए सत्र 2026-27 के लिए बिजली का नया टैरिफ तय करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बिजली नियामक आयोग में याचिका लगाई है। कंपनी ने छह हजार करोड़ का घाटा बताया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल भी महंगी बिजली का झटका लगेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी ने राज्य में बिजली की दरें बढ़ाने के लिए नया टैरिफ प्लान भी विद्युत नियामक आयोग में जमा किया है। प्रस्तावित टैरिफ में औसतन 24 प्रतिशत तक वृद्धि का सुझाव दिया गया है। विद्युत कंपनी के इस प्रस्ताव पर नियामक आयोग समीक्षा करेगी। साथ ही आम उपभोक्ताओं और संबंधित पक्षों से दावा-आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत जनसुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसमें उपभोक्ता अपनी राय और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। जनसुनवाई के बाद नियामक आयोग अंतिम निर्णय लेगा। नियमों के मुताबिक पॉवर कंपनी को दिसंबर माह में नए सत्र के टैरिफ के लिए याचिका लगानी रहती है। पॉवर कंपनी ने आयोग से 31 दिसंबर तक का समय याचिका लगाने के लिए मांगा था। इसके एक दिन पहले ही 30 दिसंबर को पॉवर कंपनी ने अपनी याचिका लगाई। इस याचिका में पूरा लेखा-जोखा देते हुए पॉवर कंपनी ने बताया है कि नए सत्र 2026-27 में उसको कितने का राजस्व मिलेगा और उसका खर्च कितना है। इस सत्र के फायदे के साथ पुराना घाटा भी बताया गया है।

राष्ट्रपति से मिले सीएम साय

रायपुर,03 जनवरी 2026। सीएम विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव 'बस्तर पंडुम 2026' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति को बस्तर अंचल की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति, परंपराओं एवं लोक जीवन से अवगत कराते हुए कहा कि बस्तर पंडुम राज्य की जनजातीय विरासत के संरक्षण, संवर्धन और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह आयोजन तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसका अंतिम चरण फरवरी 2026 में बस्तर में संपन्न होगा।

CGPSC घोटाला....400 पन्नों की फाइनल चार्जशीट पेश,29 लोग बने आरोपी

रायपुर,03 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CGPSC घोटाला 2021 मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए अपनी फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस विस्तृत रिपोर्ट में कुल 29 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी ने खुलासा किया है कि इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में न केवल प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, बल्कि शिक्षा माफियाओं का भी बड़ा हाथ था। इस सूची में एक प्रमुख कोचिंग संचालक का नाम जुड़ने से मामला और भी गंभीर हो गया है। सीबीआई की इस कार्रवाई ने राज्य के प्रशासनिक गलियारों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच सनसनी फैला दी है।

महासमुंद के होटल में रची गई साजिश : सीबीआई की चार्जशीट में महासमुंद जिले के बारनवापारा स्थित एक होटल का जिक्र किया गया है, जो इस घोटाले का मुख्य केंद्र बना था। जांच के अनुसार, एक कोचिंग संचालक के पास परीक्षा से पहले

ही CGPSC 2021 का प्रश्नपत्र पहुँच गया था। इस संचालक ने संदिग्ध अभ्यर्थियों को गुपचुप तरीके से इस होटल में इकट्ठा किया और उन्हें वास्तविक पर्चे के आधार पर पूरी तैयारी करवाई। यह 'क्रैश कोर्स' सामान्य शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि लीक हुए प्रश्नपत्र को रटाने के लिए आयोजित किया गया था। इस खुलासे ने परीक्षा की शुचिता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं और यह स्पष्ट कर दिया है कि चयन प्रक्रिया को किस तरह से हाईजैक किया गया था।

भाई-भतीजावाद का चरम

CGPSC 2021 के परिणाम जब 2023 में घोषित हुए, तभी से ये विवादों के घेरे में थे। जांच में पाया गया कि मेरिट सूची के टॉप-20 में से 13 से अधिक अभ्यर्थी किसी न किसी बड़े अधिकारी, प्रभावशाली नेता या रसूखदार कारोबारी के बेटे, बहू या करीबी रिश्तेदार थे। सबसे चौंकाने वाला नाम तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी का है। उनके दत्तक पुत्र और परिवार के तीन से अधिक सदस्यों का चयन सीधे तौर पर डिप्टी कलेक्टर और अन्य उच्च पदों पर हुआ था। इस धांधली में प्रभावशाली कारोबारी प्रकाश गोयल का परिवार भी शामिल था, जिनके बेटे और बहू ने डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया था। सीबीआई ने इन सभी लाभार्थियों को अब आरोपी की श्रेणी में खड़ा कर दिया है।

आरती वासनिक की भूमिका: परीक्षा नियंत्रक पर पर्चा लीक करने का आरोप : इस पूरे सुनियोजित घोटाले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण और संदिग्ध माना गया है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरती वासनिक को मुख्य आरोपियों में से एक बनाया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, लोक सेवा आयोग के भीतर से प्रश्नपत्र को बाहर निकालने और उसे कोचिंग संचालकों तक पहुँचाने में वासनिक ने 'मास्टरमाइंड' की तरह काम किया। एक परीक्षा नियंत्रक, जिसकी जिम्मेदारी गोपनीयता बनाए रखना थी, वही इस पेपर लीक कांड की धुरी निकली। उनकी मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर गोपनीयता का भंग होना संभव नहीं था।

नकली वन भैंसा...वन विभाग ने सरकार और छत्तीसगढ़ की भोली-भाली जनता को बनाया बेवकूफ

रायपुर,03 जनवरी 2026। बीस साल से छत्तीसगढ़ वन विभाग वन भैंसों के संरक्षण-संवर्धन पर करोड़ों खर्च चुका है। उदंती-सीता नदी टाइगर रिजर्व में बाड़े में रख कर वन भैंसे के बच्चों को जन्म दिलवाया। पूरे समय जनता को बताते रहे कि इनकी संख्या बढ़ रही है और अब पता चला है कि दस दिन पहले वन विभाग ने इन्हें हाइब्रिड वन भैंसों बता कर उदंती-सीता नदी टाइगर रिजर्व से 100 किलोमीटर दूर बाहर खदेड़ दिया है। कुछ जानकार लोग बता रहे हैं कि उन्हें उड़ीसा में ले जाकर छोड़ दिया गया है, ताकि ये वापस नहीं आ पाएं। रायपुर के वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(वन्यप्राणी) से प्रश्न पूछे हैं। 2007 में एक ग्रामीण से वन विभाग जबरदस्ती आशा नामक मादा को ले कर आए, इसे शुद्ध नस्ल का बताया गया। आशा ने राजा, प्रिंस, मोहन, वीरा, सोमू, खुशी और हीरा को जन्म दिया। बाद में रु. सत्ताईस हजार में विभाग ने ग्रामीणों से रंभा और मेनका नाम की दो क्रॉस मादा खरीदी। रंभा और मेनका ने मालती और भानुमति को जन्म दिया। चारों ने पार्वती, विष्णु, दुर्गा,किरण,कान्हा,प्रह्लाद,रवि, सोमवती, जानकी, उर्वशी और सूर्या (15 से ज्यादा) को जन्म दिया। वन विभाग को पहले दिन से ही पता था कि आशा सहित ये सभी हाइब्रिड वन भैंसे हैं। रंभा और मेनका की खरीदी के कागज में ही लिखा है कि दोनों क्रॉस ब्रीड हैं। वन विभाग की पोल तब खुली जब केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इन वन भैंसों को हाइब्रिड बता कर, असम के प्योर ब्रीड वन भैंसों के साथ प्रजनन के लिए स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अचानक वन विभाग को समझ में आया और उसे भारत के संविधान की याद आई। अनुच्छेद 48(ए) और 51(ए)(जी) के प्रावधानों का हवाला देते हुए, उप निदेशक यूएसटीआर ने सभी हाइब्रिड वन भैंसों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा। बाद में अक्टूबर 2023 में इन्हें बाड़े से भगा दिया बताया गया – बताया गया कि बाड़ा तोड़कर भाग गए। भागने के बाद, यूएसटीआर में बड़ी संख्या में गांव होने के कारण, इन हाइब्रिड वन भैंसों ने कुछ फसल नुकसान पहुंचाया।

वकील की बेटी ने किया सुसाइड,परिजन सदमे में

दुर्ग,03 जनवरी 2026। जिले में 16 साल की नाबालिग लड़की ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पंचनामा कार्रवाई के बाद मर्चुरी भिजवाया गया है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें किशोरी ने अपने माता-पिता से माफी मांगी है। यह मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर स्थित बौद्ध कुटीर के पास की है। पुलिस ने बताया कि 16 वर्षीय निष्ठा गोस्वामी पिता अनिल गोस्वामी शुक्रवार की दोपहर के वक्त अपने कमरे में पढ़ाई करने गई थी। लेकिन देर शाम तक वह बाहर नहीं आई। जब ज्यादा देर हो गया तो

परिवार वालों ने दरवाजा खटखटाया। कोई आवाज नहीं आने पर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो देखा कि किशोरी फंदे पर लटकी हुई थी। निष्ठा के पड़ोसियों ने बताया कि घर में पिता अनील गोस्वामी सरकारी वकील हैं। माता भी शासकीय शिक्षक हैं। निष्ठा की एक बहन भी है। जब यह घटना हुई उस वक्त घर में दादी थी। माता-पिता नहीं थे। घटना की सूचना मिलते ही सभी तत्काल घर पहुंचे।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2023-2025-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)